कीमतें और मुद्रास्फीति

05

अध्याय

जैसे ही महामारी के दूसरे वर्ष में आर्थिक गतिविधियों ने तेजी के संकेत दिखाना शुरू किया, वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति की नई चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड़-19 से संबंधित प्रोत्साहन खर्च के साथ-साथ उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने वाली मांग ने कई उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और आपूर्ति में कटौती से मांग में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

घरेलू मोर्चे पर, भारत में औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.2 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत थी और दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत पर दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अधिक वृद्धि नहीं दर्ज की गई क्योंकि सरकार द्वारा आपूर्ति के संबंध में की गई त्वरित व्यवस्था के कारण खाद्य कीमतों में काफी कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान 2.9 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) पर अनुकूल बनी रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी। सब्जियों के मामले में, प्याज और आलू की कीमतें नियंत्रण में रहीं, हालांकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण सितंबर से नवंबर 2021 के दौरान टमाटर की खुदरा कीमतों में तेजी देखी गई। हालांकि, दिसंबर में बाजार में ताजा आवक के साथ, टमाटर की खुदरा कीमतों में भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। जबकि सब्जियों के मामले में मौसमीपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बेमौसम बारिश जैसे आकस्मिक झटके भी उनकी उपलब्धता और कीमतों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रभावी परिवहन बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित शीत भंडारण श्रृंखलाओं (कोल्डस्टोरेजचेंस) के एक मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता है। प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा। दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए थे, जो इन वस्तुओं में आयातित मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाते हुए उच्च मुद्रास्फीति को इंगित करते थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी और बाद में अधिकांश राज्यों द्वारा वैट में की गई कटौती से भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने में मदद मिली है।

थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों के कमजोर होने, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आने और कमजोर मांग के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत ही अनुकूल रहने के बाद, वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 12.5 प्रतिशतकी दर से तेज वृद्धि देखी गई। यह आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल और अन्य आयातित आदानों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि और उच्च माल ढुलाई लागत

के कारण था। वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के बीच परिणामी विचलन चर्चा का विषय बना रहा। इस विचलन को आधार प्रभाव के कारण भिन्नता, दायरे में अंतर और दो सूचकांक कवरेज में अंतर, उनके मूल्य संग्रहण, सम्मिलित की गई वस्तुएं और वस्तु भार में अंतर जैसे कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अलावा, थोक मुद्रास्फीति-आयातित इनपुट द्वारा उत्प्रेरित लागत-वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील है। थोक मुद्रास्फीति में आधार प्रभाव के धीरे-धीरे कम होने के साथ, खुद्रा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति में अंतर भी कम होने की उम्मीद है।

वैश्विक मुद्रास्फीति

5.1 2021 में, वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई। मुख्य रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवारों को विवेकानुदान वितरण/हैंडआउट्स के रूप में, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने वाली मांग के साथ, कोविड़-19 संबंधित प्रोत्साहन खर्च ने उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति दर वर्ष 2020 की 0.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में लगभग 3.1 प्रतिशत हो गई (चित्र 1)(आईएमएफ, 2022)। एनर्जी/ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और इनपुट कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और दुनिया भर में बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन (ओपेक+) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और आपूर्ति में कटौती से मांग में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी वर्ष के दौरान तेजी देखी गई।

चित्र 1: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दरें

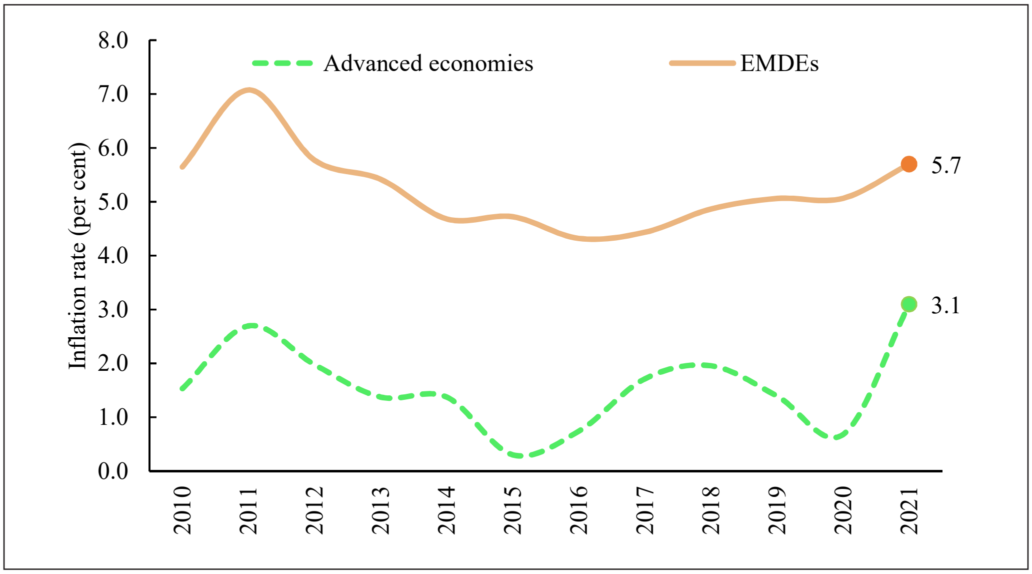

स्रोत: विश्व आर्थिक/वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, जनवरी-2022 अपडेट, आईएमएफ

नोट: 'आंकड़े वार्षिक औसत हैं;

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 40 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

5.2 हालांकि, कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हाल के महीनों में, नवंबर 2021 में 4.9 प्रतिशत और दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत तक सीमाबद्ध तरीके से सक्रिय रही जिसका सारा श्रेय सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों को जाता है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 1982 के बाद सबसे अधिक है, जिसके लिए मुख्य रुप से पुराने वाहनों और ऊर्जा को जिम्मेदार माना गया। जबकि यूके में यह मुख्य रूप से ईंधन, पुरानी कारों, आवास और घरेलू सेवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण नवंबर 2021 में 10 साल के उच्च स्तर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। उभरते बाजारों में, ब्राजील में भी 2021 के दौरान मुद्रास्फीति में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई जो दिसंबर 2021 में 10.1 प्रतिशत को छू गई। तुर्की में मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 36.1 प्रतिशत तक पहुंचकर दोहरे अंकों में रही है। (चित्र 2)। अर्जेंटीना ने पिछले छह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी देखी है।

चित्र 2: चुनिंदा देशों और भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

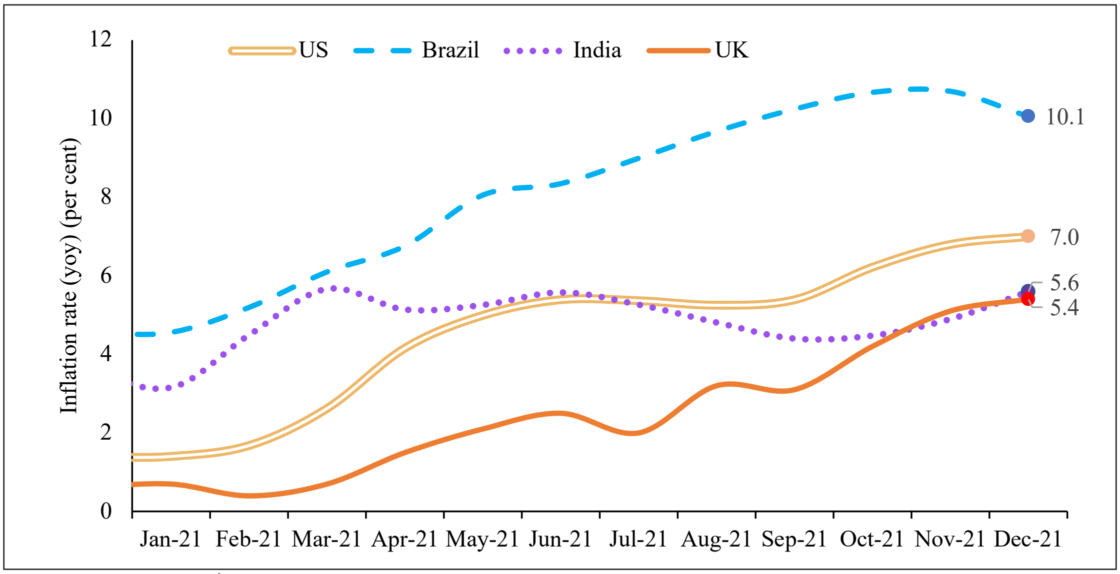

स्रोत: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

घरेलू मुद्रास्फीति

5.3 चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, कोविड-19 प्रतिबंधों, लॉक-डाउन और रात्रि कर्फ्यू के कारण उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की वजह से 2020-21 में 6 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत (तालिका 1) रही। थोक मूल्य सूचकांक पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अनुकूल रहने के बाद, 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान तेजी से बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति में देखी गई वृद्धि के लिए पिछले वर्ष में निम्न आधार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, बढ़ती इनपुट लागत और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों ने भी थोक कीमतों में वृद्धि में काफी योगदान दिया।

तालिका 1: विभिन्न मूल्य सूचकांकों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22*
डबल्यूपीआई	-3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	1.3	0.0	12.5
सीपीआई-सी (हेडलाइन मुद्रास्फीति)	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	6.6	5.2
सीपीआई - आई डबल्यूरु	5.6	4.2	2.9	5.6	7.3	5.2	5.2	5.0
सीपीआई - एएल	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	5.5	7.0	3.2
सीपीआई - आरएल	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	5.5	6.8	3.5

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग, और डबल्यूपीआई के लिए आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), सीपीआई-सीके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सीपीआई-आईडबल्यू (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक), सीपीआई-एएल (कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और सी पी आई-आरएलके लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: 2020-21 के लिए रुसीपीआई-आईडबल्यू मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016=100 पर आधारित है; (पी) - अनंतिम; सी का अर्थ संयुक्त है, आई डबल्यू का अर्थ औद्योगिक श्रमिक है, एल का अर्थ कृषि श्रमिक है और आरएल का अर्थ ग्रामीण श्रमिक है। *2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल, आरएल (अप्रैल से नवंबर)

^2020-21 (अप्रैल से दिसंबर) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल, आरएल (अप्रैल से नवंबर)

मुद्रास्फीति और इसके चालकों में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

खुदरा मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियाँ

5.4 औसत खुदरा मुद्रास्फीति जो 2019-20 में 4.8 प्रतिशत थी, 2020-21 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो कि कोविड्-19 से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण थी। जुलाई 2021 से, खुदरा मुद्रास्फीति 1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत +/- 2 प्रतिशत अंक की लक्षित सीमा के भीतर है। (तालिका 2)। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 6.6 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई है।

5.5 2021-22 में, मुख्य रुप से खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति, 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसतन 2.9 प्रतिशत के निचले स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी। जुलाई और सितंबर 2021 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई। हालांकि बढ़त के साथ, यह दिसंबर 2021 में बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गई।

5.6 चालू वित्त वर्ष के दौरान, खुदरा मूल मुद्रास्फीति ('खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' को छोड़कर मुद्रास्फीति-सूचकांक के अस्थायी घटक) में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है। अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के लिए औसत कोर मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.4 प्रतिशत के मुकाबले 5.9 प्रतिशत थी और अधिकांश महीनों के दौरान 6 प्रतिशत से नीचे रही। (चित्र 3)।

तालिका 2: सीपीआई-आधार 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22#	अप्रैल-21	मई-21	जून-21	जुलाई-21	अगस्त-21	सितंबर-21	अक्तूबर-21	नवंबर-21	दिसंबर-21(पी)
समस्त समूह	100	4.8	6.2	6.6	5.2	4.2	6.3	6.3	5.6	5.3	4.3	4.5	4.9	5.6
सीएफपीआई*	39.1	6.7	7.7	9.1	2.9	2.0	5.0	5.1	4.0	3.1	0.7	0.8	1.9	4.0
खाद्य और पेय पदार्थ	45.9	6.0	7.3	8.4	3.5	2.6	5.2	5.6	4.5	3.7	1.6	1.8	2.6	4.5
अनाज और उत्पाद	9.7	2.8	3.8	5.2	-0.6	-3.0	-1.4	-1.9	-1.7	-1.4	-0.6	0.4	1.5	2.6
मांस मछली	3.6	9.3	15.4	16.3	8.0	16.7	9.1	4.8	8.3	9.2	8.0	7.1	5.5	4.6
अंडे	0.4	4.5	12.9	13.3	9.3	10.6	15.2	19.4	20.8	16.3	7.1	-1.4	-1.3	1.5
दुग्ध व दूध के उत्पाद	6.6	2.9	5.4	6.4	2.4	-0.1	0.6	1.9	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.8
तेल और वसा	3.6	2.9	16.0	14.0	30.9	25.9	30.9	34.8	32.5	33.1	34.2	33.6	29.7	24.3
फल	2.9	0.7	2.6	1.4	7.4	9.7	11.8	11.8	9.0	6.7	3.6	4.9	6.0	3.5
सब्जियाँ	6.0	21.3	5.8	11.0	-11.3	-14.5	-1.9	-0.7	-7.8	-11.7	-22.4	-19.4	-13.6	-3.0
दालें और उत्पाद	2.4	9.9	16.4	17.6	7.1	7.5	9.4	10.0	9.0	8.8	8.7	5.4	3.2	2.4
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.4	0.8	2.5	3.5	1.3	-6.0	-1.5	0.8	-0.5	-0.6	3.0	5.4	6.2	5.6
ईंधन और प्रकाश	6.8	1.3	2.7	2.3	12.2	8.0	11.9	12.6	12.4	12.9	13.6	14.3	13.3	11.0
खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर (कोर) सीपीआई	47.3	4.0	5.5	5.4	5.9	5.3	6.6	6.1	5.8	5.8	5.9	5.9	6.2	6.0

स्त्रोत: सीएसओपी : अनंतिम *उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
^अप्रैल से दिसंबर 2020 #अप्रैल से दिसंबर 2021

चित्र 3: सीपीआई-सी हेडलाइन, मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान/प्रवृत्तियाँ

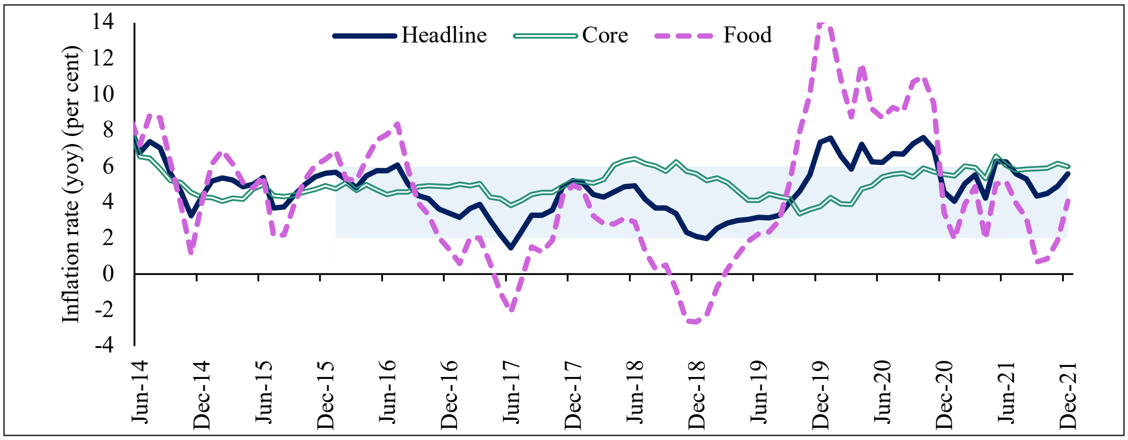

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

5.7 परंपरागत रूप से, मूल मुद्रास्फीति की गणना समग्र मुद्रास्फीति से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश'[1] समूहों को छोड़कर की जाती है। जबकि सीपीआई-सी में, 'वाहन के लिए पेट्रोल' और 'वाहन के लिए डीजल' जैसी प्रमुख ईंधन वस्तुएं, जिनका वजन अपेक्षाकृत अधिक होता है, उन्हें 'ईंधन और प्रकाश' में शामिल

[1]'ईंधन और प्रकाश' में मुख्य रूप से घरों द्वारा अपनी घरेलू ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली मदें शामिल हैं, जिसमें बिजली, एलपीजी, मिट्टी के तेल और खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य ईंधन जैसे वाहन शामिल नहीं हैं। दूसरी ओर, वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल विविध समूह के 'परिवहन और संचार' उप-समूह में शामिल हैं।

नहीं किया जाता है। इन ईंधन मदों को 'परिवहन और संचार' में शामिल किया जाता है जो कि 'विविध' समूह के तहत एक उपसमूह होता है। इसलिए, कोर मुद्रास्फीति से अस्थिर ईंधन वस्तुओं को बाहर करने के बजाय, खुदरा मूल मुद्रास्फीति की गणना करने का पारंपरिक तरीका, मूल मुद्रास्फीति में अस्थिर ईंधन वस्तुओं को शामिल करना जारी रखता है। नतीजतन, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित करती रहती है।

5.8 इस विसंगति को दूर करने के लिए 'खाद्य और पेय पदार्थ' तथा 'ईंधन और प्रकाश' के अलावा, 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल' और 'वाहनों के लिए स्नेहक/लुब्रिकंट्स और अन्य ईंधन' हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति से निकालकर 'परिष्कृत' मूल मुद्रास्फीति का निर्माण किया गया है। पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति और परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति दोनों को चित्र 4 में प्रस्तुत किया गया है। जून 2020 से, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति से काफी नीचे रही है, जो पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति उपाय में ईंधन वस्तुओं में मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाती है।

चित्र 4: रिटेल कोर और 'रिफाइंड कोर' मुद्रास्फीति

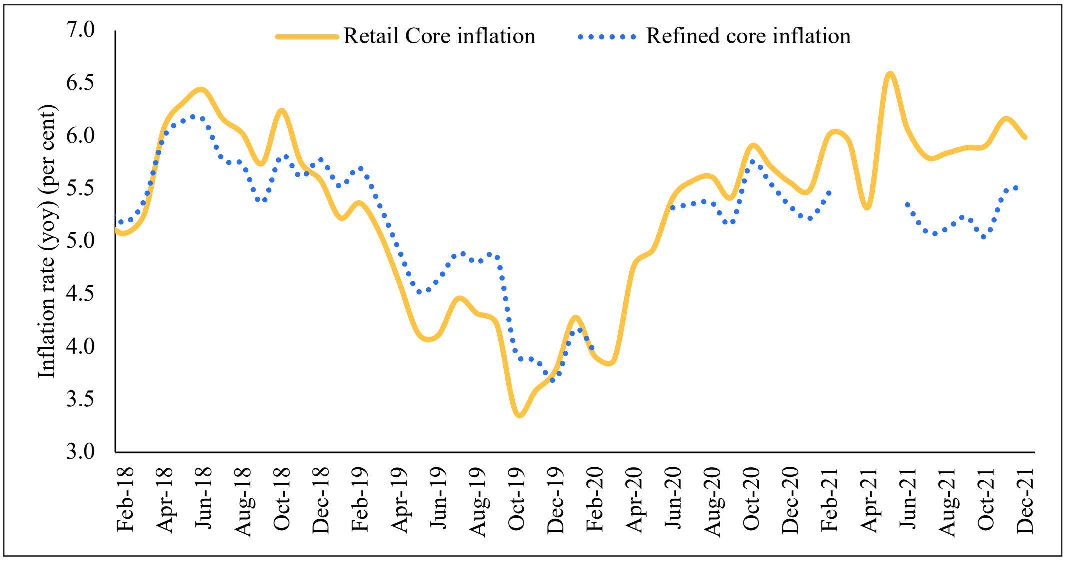

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल' और 'वाहनों के लिए स्नेहक/लुब्रिकंट्स और अन्य ईंधन' के लिए आइटम/मद स्तर सूचकांक मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं थे।

खुदरा मुद्रास्फीति किससे प्रेरित है और क्यों?

5.9 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के विपरीत, जब 'खाद्य और पेय पदार्थों' ने मुद्रास्फीति उत्पन्न की, 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में 'विविध' और 'ईंधन और प्रकाश' समूह रहा है। 'विविध समूह' का योगदान 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 35 प्रतिशत हो गया है और 'ईंधन और प्रकाश' का योगदान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 5) दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान, 'खाद्य और पेय पदार्थों' का योगदान 59 प्रतिशत से घटकर 31.9 प्रतिशत हो गया। 'विविध समूह' के भीतर, उप-समूह 'परिवहन और संचार' का सबसे अधिक योगदान रहा, उसके बाद स्वास्थ्य का योगदान रहा।

चित्र 5: 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) और 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में समग्र सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में समूहों का प्रतिशत में योगदान

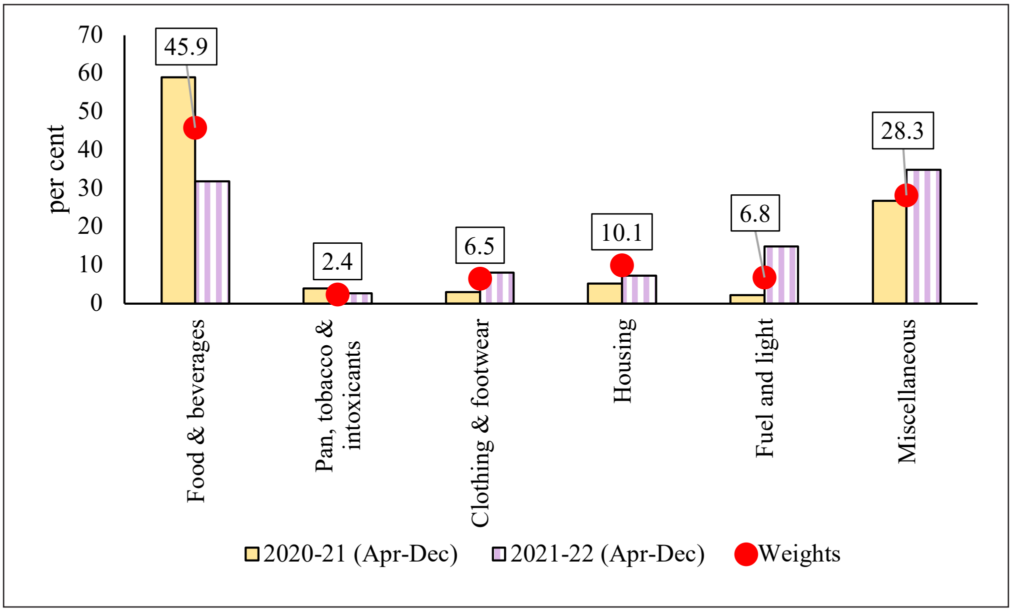

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

'ईंधन और प्रकाश' और 'परिवहन और संचार': 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में, 'ईंधन और प्रकाश' और 'परिवहन और संचार' में मुद्रास्फीति ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद की उच्च कीमतों और उच्च करों (चित्र 6) द्वारा संचालित थी। अप्रैल 2020 में, कोविड़-19 प्रेरित प्रतिबंधों के कारण वैश्विक मांग में कमी के प्र्युत्तर में, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत 19.9 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई। हालांकि, इसके बाद, कीमतें बढ़ रही हैं (चित्र 7)। ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति में अभूतपूर्व कटौती के कारण कीमतों का ऊपर की ओर रुझान था। 2021 में भी ऊपर की ओर रुझान जारी रहा, क्योंकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोविड़-19 प्रतिबंध में ढील के साथ मांग में तेजी आई। इसके अलावा, ओपेक+ देशों द्वारा पिछले साल किए गए उत्पादन में कटौती धीरे-धीरे की गई है और मांग में सुधार के साथ तालमेल नहीं रखा गया है। हालांकि, अक्टूबर 2021 की दूसरी छमाही के बाद से यूरोप में बढ़ते कोविड़-19 मामलों और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की बहाली की संभावना सहित अन्य कारकों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रही है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा वैट में की गई कटौती के कारण 2021 में भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में भी कमी आई है (चित्र 8)। हालांकि, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मंद होती आपूर्ति (टाइट सप्लाई) के कारण जनवरी 2022 में कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी देखी गई।

चित्र 6: 'ईंधन और प्रकाश/लाइट' और 'परिवहन और संचार' मुद्रास्फीति

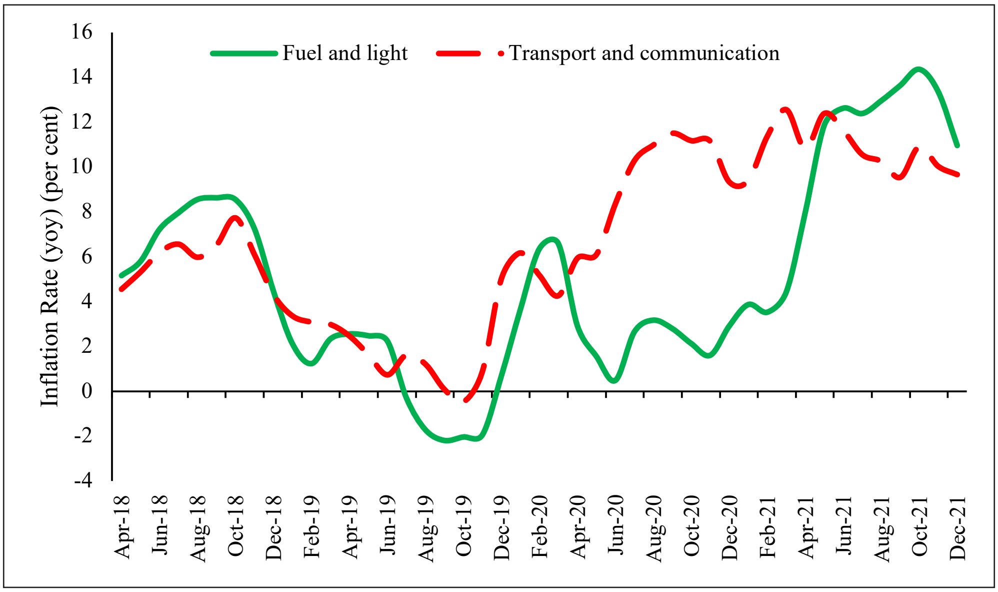

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

चित्र 7: कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (भारतीय बास्केट)

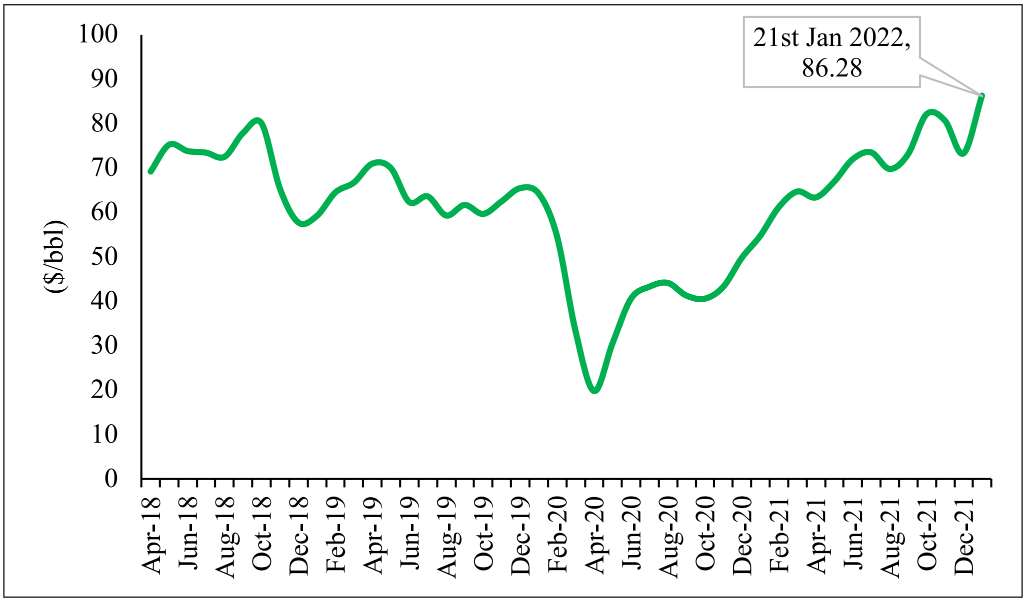

स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी

चित्र 8: चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी)

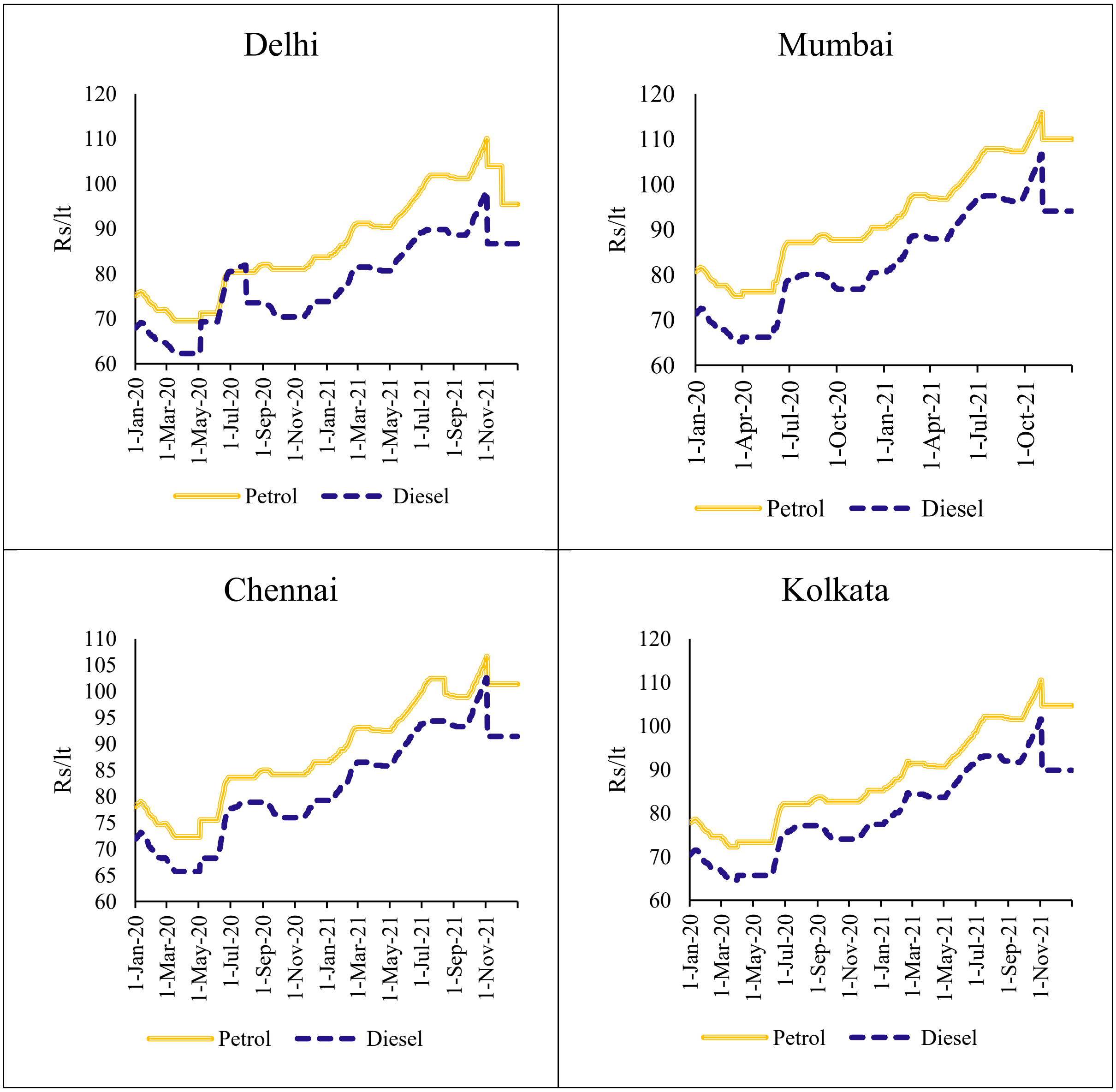

स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी

5.11 **विविध:** 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 'विविध' समूह, जो समग्र मुद्रास्फीति का लगभग 35 प्रतिशत है, खुदरा मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस समूह में भीतर, मुख्य रूप से वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल में मुद्रास्फीति जो उपसमूह 'परिवहन और संचार' में आते हैं। उच्च मुद्रास्फीति में ज्यादा योगदान दे रही है। 'कपड़े और जूते' से संबंधित मुद्रास्फीति में भी चालू वित्त वर्ष के दौरान एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई जो संभवत: उच्च उत्पादन और इनपुट लागत (आयातित इनपुट सहित) के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में पुन: बढ़ोत्तरी की वजह से है।

5.12 **'खाद्य और पेय':** खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक 8 प्रतिशत से ऊपर रही, लेकिन उसके बाद इसमें 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति वृद्धि दर्ज करते हुए गिरावट आई।अनाज और उत्पादों में मुद्रास्फीति अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान नकारात्मक रही और अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कम रही, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे

नीचे की 67 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित अनाज की पर्याप्त आपूर्ति इंगित करती है।

5.13 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान, 'सब्जियों' में मुद्रास्फीति (-)11.3 प्रतिशत पर नकारात्मक रही; जिसका समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में नकारात्मक योगदान रहा। हालांकि, टमाटर की कीमतें सितंबर 2021 के अंत के बाद भी बढ़ीं, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के उत्पादक राज्यों में बेमौसम भारी बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ और मंडी में उपज के आगमन में देरी भी हुई। प्याज और आलू की महंगाई पूरे साल नकारात्मक रही। उत्पादक राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश के कारण टमाटर की आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर की कीमतों पर दबाव और बढ़ गया। दिसंबर 2021 में ताजा आपूर्ति के आने से टमाटर की कीमतों में नरमी आई है। प्याज और आलू की मुद्रास्फीति पूरे वर्ष नकारात्मक रही। मौसमी और अन्य बाहरी कारक टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं (बॉक्स 1)।

5.14 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान प्रोटीन आधारित वस्तुओं जैसे 'मांस और मछली' में मुद्रास्फीति काफी अधिक रही, क्योंकि कोविड़-19 संबंधित आपूर्ति में व्यवधान और सोयाबीन भोजन की उच्च कीमतों के कारण पोल्ट्रीफीड की ऊंची कीमतें थीं। जबकि 'मांस और मछली' की औसत मुद्रास्फीति 2020-21 में 15.4 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 8.0 प्रतिशत कम रही है। सितंबर 2021 से 'मांस और मछली' की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, और दिसंबर 2021 में यह 4.6 प्रतिशत थी, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान सबसे कम थी। अंडे की मुद्रास्फीति में जुलाई 2021 से लगातार गिरावट देखी गई है, और अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में नकारात्मक बनी हुई है। 'दालों और उत्पादों' की मुद्रास्फीति पिछले वित्त वर्ष में उच्च बनी रही, हालांकि, सरकार के आपूर्ति व्यवस्था संबंधी सक्रिय प्रयासों के कारण जुलाई 2021 से इसमें लगातार गिरावट आई है।

बॉक्स 1: टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों में मौसमी अनियमितता

उत्पादन में मौसमी तत्व और अनियमित आघात/शॉक दो महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो कृषि वस्तुए खासकर टमाटर और प्याज जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव में योगदान करते हैं। कीमतों में बदलाव, एक वर्ष के विभिन्न महीनों के दौरान इन वस्तुओं के उत्पादन के अलग-अलग पैटर्न का परिणाम है। दूसरी ओर, आघात/शॉक अक्सर अनिश्चित मौसम की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हालाँकि, इन दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति को कम से कम मूल्य वृद्धि के अधिक निश्चित मौसमी पैटर्न को समझने की दिशा में उन्मुख किया जा सकता है।

प्रायः एक समय श्रृंखला में चार घटक होते हैं: प्रवृत्ति, चक्र, मौसमीपन और अनियमितता। प्रवृत्ति, कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि या गिरावट का संकेत देती है। एक चक्र कीमतों में वृद्धि या गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निश्चित आवृत्ति के नहीं होते हैं जैसे कि व्यापार चक्र का प्रतिनिधित्व करना। मौसमीपन, निश्चित आवृत्ति का होता है और वर्ष के दौरान विशेष समय पर होता है। कीमतों में मौसमी कृषि वस्तुओं के उत्पादन के मौसमी पैटर्न या मांग में मौसमी जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण हो सकती है। प्रवृत्ति, चक्र और मौसमी घटकों को हटाने के बाद एक समय श्रृंखला में शेष राशि अनियमित घटक है। इसका परिमाण, प्रभाव और अवधि अप्रत्याशित एक प्राथमिकता है।

वर्तमान विश्लेषण के लिए, वर्ष के विभिन्न महीनों में इन वस्तुओं में मौसमीपनकी पहचान करने के लिए कीमतों का मौसमी घटक निकाला जाता है। दूसरी ओर, अनियमित घटक का उपयोग उस समय के बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जब विभिन्न बहिर्जातआघात/शॉक, वस्तुओं की कीमतों में उछाल का कारण बनते हैं। लोएस (एसटीएल) (क्लीवलैंडएटअल।, 1990) पर आधारित मौसमी-प्रवृत्ति अपघटन प्रक्रिया का उपयोग अपघटन

के लिए किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर मासिक खुदरा मूल्य के आंकड़े उपभोक्ता मामले विभाग से लिए गए हैं। चित्र-1ए टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों के रुझान को दर्शाता है।

चित्र 1ए: टमाटर और प्याज के खुदरा मूल्य

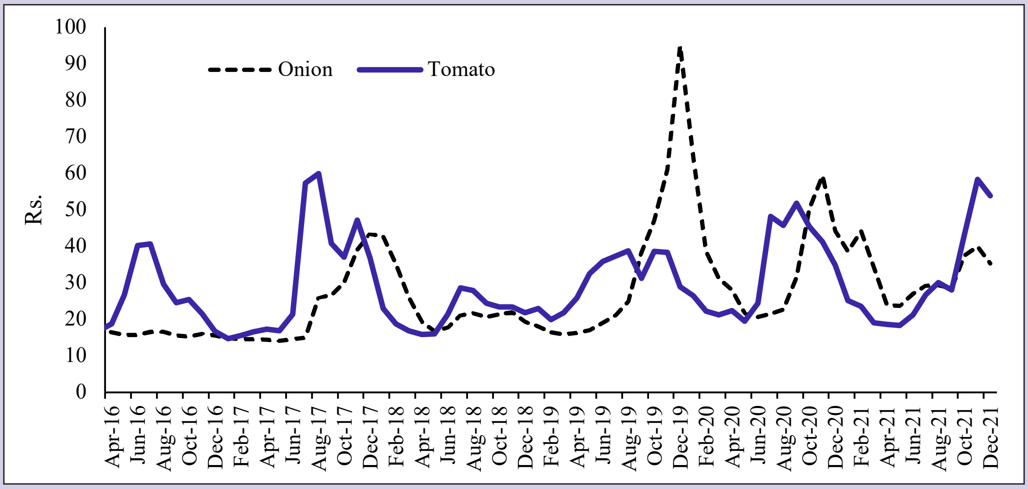

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग

1. टमाटर:

टमाटर में मौसमी तत्व:

मौसमी घटक हर साल जुलाई से नवंबर के दौरान टमाटर की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालते हैं; जुलाई में ऊपर की ओर दबाव सबसे अधिक रहता है (चित्र 1बी)। दूसरी ओर, मौसमी कारक मार्च में कीमतों पर सबसे अधिक दबाव डालता है। कीमतों में यह मौसमीपन टमाटर के उत्पादन के मौसमी पैटर्न के परिणामस्वरूप आता है, क्योंकि टमाटर का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन रबी मौसम के दौरान ही होता है: अक्टूबर-फरवरी के दौरान रोपाई और दिसंबर-जून के दौरान फसल तैयार होती है। जुलाई-नवंबर के दौरान खरीफ उत्पादन आमतौर पर एक वर्ष में टमाटर के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत से भी कम योगदान देता है। आपूर्ति में यह भिन्नता हर साल जुलाई-नवंबर के दौरान टमाटर की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालती है। अगर अनियमित आघात/शॉक नहीं होते तो मौसमीपन के कारण टमाटर की कीमतें लंबी अवधि के रुझान की तुलना में मार्च 2021 की तुलना में जुलाई 2021 में करीब 15 रूपये अधिक होती।

चित्र 1बी: टमाटर के खुदरा मूल्यों में मौसमीपन

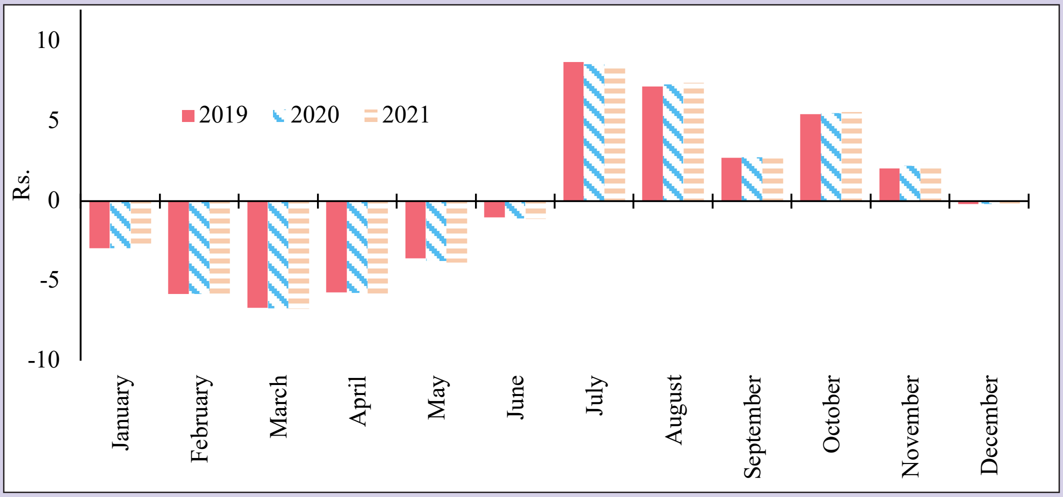

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

टमाटर की कीमतों में अनियमित प्रभाव:

चित्र 1सी पिछले 5 वर्षों के दौरान टमाटर की खुदरा मूल्य श्रृंखला में अनियमित घटक प्रस्तुत करता है। चार्ट में बड़े उछाल का उपयोग कीमतों में झटके की घटनाओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। छह उदाहरणों की पहचान की गई है जब टमाटर के खुदरा मूल्य के मामले में अनियमित घटक ने एक बड़ी वृद्धि (10 रुपये के करीब या उससे अधिक) प्रदर्शित की है। कीमतों में उछाल के संभावित कारण तालिका 1ए में दिए गए हैं।

चित्र 1सी: टमाटर के खुदरा मूल्यों में अनियमित घटक

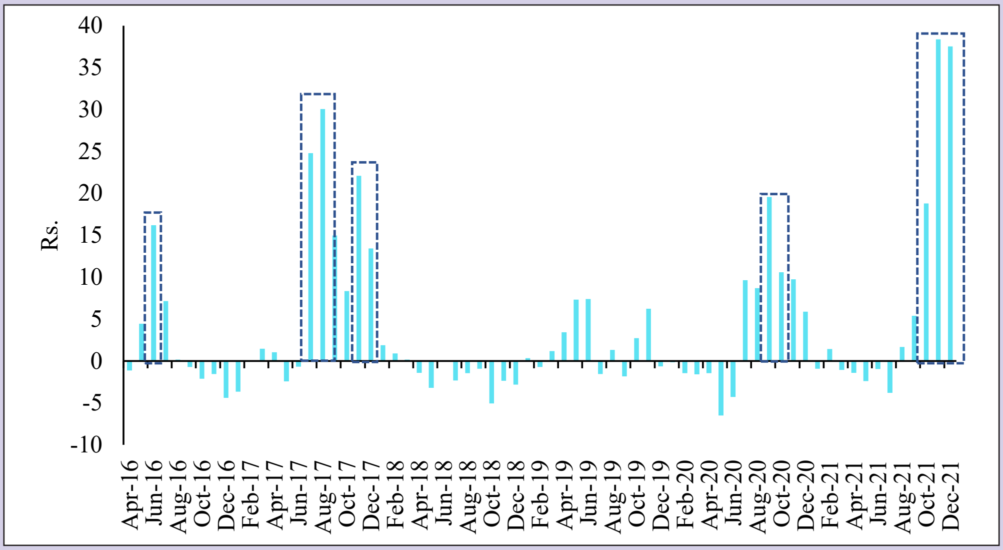

स्रोत: सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

तालिका 1ए: पिछले पांच वर्षों के दौरान टमाटर में मूल्य वृद्धि की घटनाएं

पहचानी गई घटनाएं	कारण
जून 2016	टमाटर की कम आपूर्ति, क्योंकि 2016 की रबी फसल दक्षिणी राज्यों में भीषण सूखे की स्थिति से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
जुलाई-अगस्त 2017	मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश से फसल को कुछ नुकसान हुआ है। इसके अलावा, बारिश के कारण ट्रकों के सामान्य समय से अधिक समय लेने से परिवहन में समस्या आ रही है जिससे आवक में कमी आई है। बारिश के कारण जमा हुआ स्टॉक खराब हो गया।
नवंबर-दिसंबर 2017	कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश।
मई 2019	महाराष्ट्र में देरी से कटाई के साथ-साथ कर्नाटक में फंगस से क्षतिग्रस्त फसलों ने कीमतों में शुरुआती तेजी की शुरुआत की, जो प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्यों-कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण आपूर्ति बाधित होने से बढ़ गई थी।
सितंबर 2020	भारी बारिश के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों से नई फसल की कम आवक।
नवंबर 2021	पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ और इन राज्यों से आने में देरी हुई। उत्तरी राज्यों से देरी से आवक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश हुई जिससे आपूर्ति बाधित हुई।

2. प्याजः

प्याज में मौसमीपनः

रबी सीजन, जो दिसंबर-जनवरी में रोपाई और मार्च से मई के अंत में फसल देता है। - एक वर्ष में कुल प्याज उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है। रबी फसल की अवधि के साथ मेल खाने वाली कीमतों पर मौसमी घटक नीचे की ओर दबाव (चित्र 1डी में नकारात्मक मान) और अन्य महीनों में ऊपर की ओर दबाव (सकारात्मक मान) डालते हैं तथा यह दबाव दिसंबर में चरम पर पाया जाता है। अन्य दो उत्पादन मौसमनामतः खरीफ - जुलाई-अगस्त में रोपाई और अक्टूबर-दिसंबर में फसल - और देर से खरीफ - अक्टूबर-नवंबर में रोपाई और जनवरी-मार्च में फसल, में आपूर्ति की कमी रहती हैं।

चित्र 1डीः प्याज के खुदरा मूल्यों में मौसमीपन

स्रोतः सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

प्याज की कीमतों में उछालः

प्याज के खुदरा मूल्य में अनियमित घटक जो चित्र 1ई में दिखाया गये है निरीक्षण के आधार पर कीमतों में वृद्धि की चार घटनाओं की पहचान की गई है। घटनाओं के संभावित कारण तालिका 1बी में सूचीबद्ध किए गए हैं।

चित्र 1ईः प्याज के खुदरा मूल्यों में अनियमित घटक

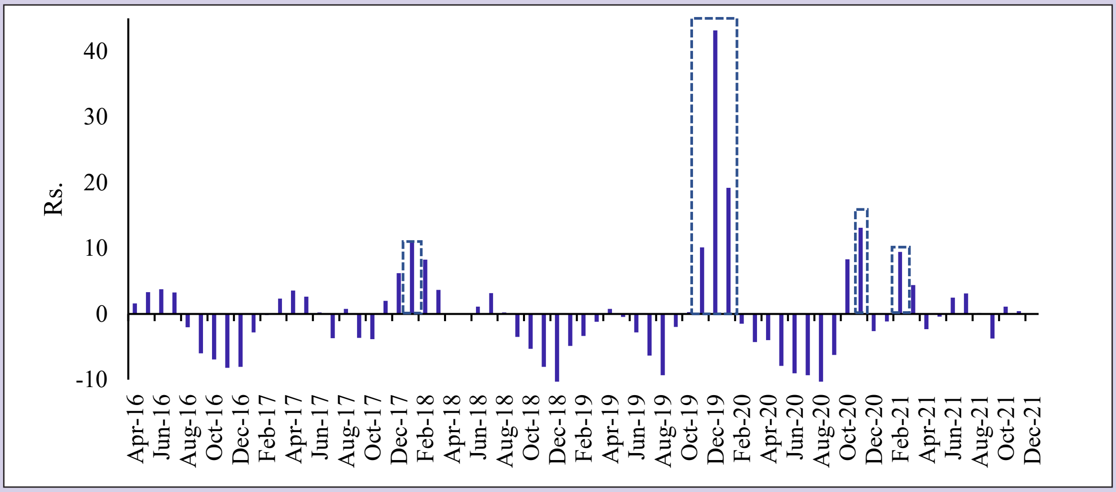

स्रोतः सर्वेक्षण गणना/समीक्षा परिकलन

तालिका 1बी: पिछले पांच वर्षों के दौरान प्याज की कीमतों में उछाल की घटनाएं

पहचानी गई घटनाएं	कारण
जनवरी 2018	पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र में मौसम की स्थिति में चक्रवात और पश्चिमी तट पर बनने वाले निम्न दबाव, शोलापुर, नासिक, अहमदनगर और लासलगांव जैसे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।
नवंबर 2019-जनवरी 2020	सितंबर और अक्टूबर 2019 के महीने में बेमौसम और लंबी बारिश ने खरीफ प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाया जिससे इसकी आपूर्ति कम हो गई और इसकी कीमतों में वृद्धि हुई।
अक्तूबर- नवंबर 2020	कर्नाटक में सितंबर में भारी बारिश हुई जो कि अक्टूबर के अंत में महाराष्ट्र से खरीफ फसल से पहले थोक आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थी ने सारा गणित खराब कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, सितंबर की बारिश ने न केवल कर्नाटक, बल्कि महाराष्ट्र से भी आपूर्ति को प्रभावित किया है, जहां अहमदनगर, नासिक और पुणे सहित प्याज बेल्ट में भारी बारिश ने पानी के रिसाव के साथ भंडारण को भी प्रभावित किया है।
फरवरी 2021	देर से आने वाली खरीफ फसल के आने में विलंब का कारण जनवरी 2021 में उत्पादक क्षेत्रों में बारिश का होना है।

निष्कर्ष

टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी में मौसमी और शॉक/आघात दोनों घटकों का योगदान रहा है। मौसमी उत्पादन पैटर्न के परिणामस्वरूप कीमतों में मौसमी नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खराब मौसम के दौरान उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए। टमाटर के अधिशेष उत्पादन के प्रसंस्करण और प्याज के प्रसंस्करण और भंडारण के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्पाद की बर्बादी में कटौती, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से भी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) बागवानी के समग्र विकास की परिकल्पना करता है और 25 टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण के प्रत्येक ढांचे के लिए 1.75 लाख रुपये प्रति यूनिट की कुल लागत के 50 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान करता है। सरकार बफर के लिए किसानों से सीधे फार्म गेट कीमतों पर प्याज भी खरीदती है। ग्रामीण गोदामों के लिए कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) जैसी योजनाएं छोटे किसानों को अपनी उपज को लाभकारी कीमतों पर बेचने और संकटपूर्ण बिक्री से बचने के लिए अपनी धारण क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। टमाटर, प्याज और आलू (टॉप/टीओपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए ष्ऑपरेशनग्रीन्सष भी है। यह अधिशेष उत्पादक क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करता है। उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से खपत या कमी वाले क्षेत्रों में फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी पालन, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा शुरू की गई थी।

5.15 समूह में केवल 7.8 प्रतिशत भार होने के बावजूद 'तेल और वसा' ने 'खाद्य और पेय पदार्थ' मुद्रास्फीति में 60 प्रतिशत का योगदान दिया। 2019 के मध्य से उप-समूह की मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है; अप्रैल 2020 से दोहरे अंकों में रहा और 2021-22 (चित्र 9) में और ऊपर की प्रवृत्ति देखी गई। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में इसकी महंगाई 30.9 फीसदी रही है, और दिसंबर 2021 में यह 24.3 फीसदी थी।

चित्र 9: तेल और वसा उपसमूह में मुद्रास्फीति

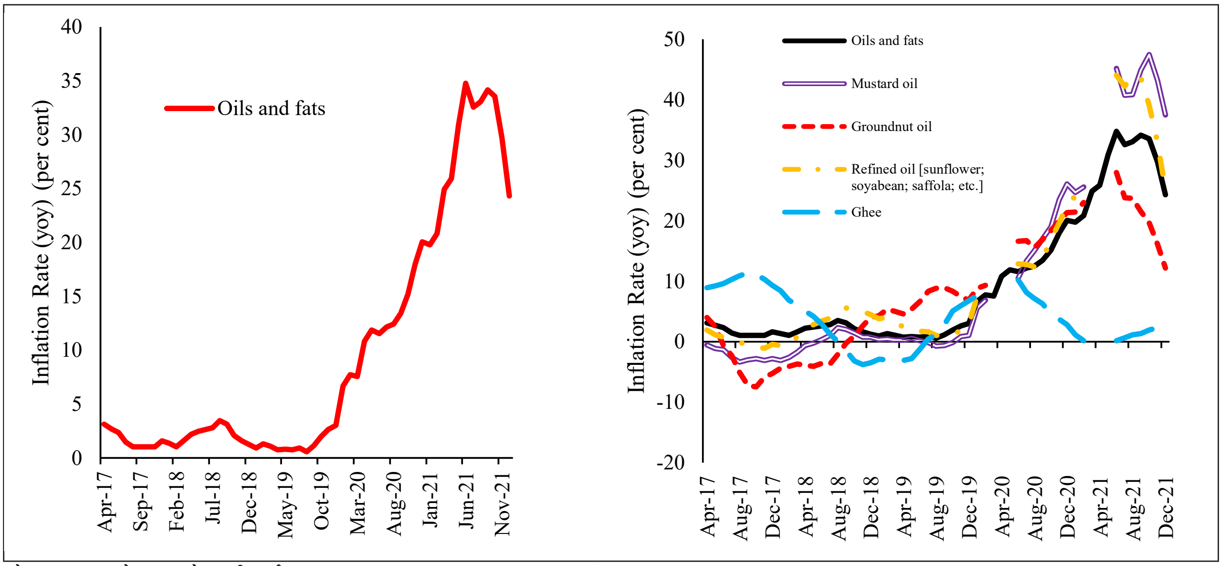

स्रोतः एनएसओ, एमओएसपीआई

नोटः मार्च-मई 2020 के लिए 'सरसों का तेल', 'मूंगफली का तेल' 'रिफाइंड तेल' और 'घी' के आइटम स्तर सूचकांक उपलब्ध नहीं थे।

5.16 भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और खाद्य तेलों के आयात का लगभग 60 प्रतिशत, पामऑइल / ताड़ का तेल (कच्चा + परिष्कृत) (पीआईबी, 2021) है। नतीजतन, आयात और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव खाद्य तेल की घरेलू कीमतों को प्रभावित करता है। खाद्य तेलों की कीमतों में मौजूदा उछाल मुख्य रूप से खाद्य तेलों की उच्च और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण है। मई 2020 से खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक के तेल घटक में वृद्धि तेज रही है, और मलेशिया में उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रवासी श्रमिकों की कमी के बीच मजबूत वैश्विक आयात मांग के कारण 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है (चित्र 10; एफएओ, 2021)।

चित्र 10: एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांकः खाद्य तेल घटक

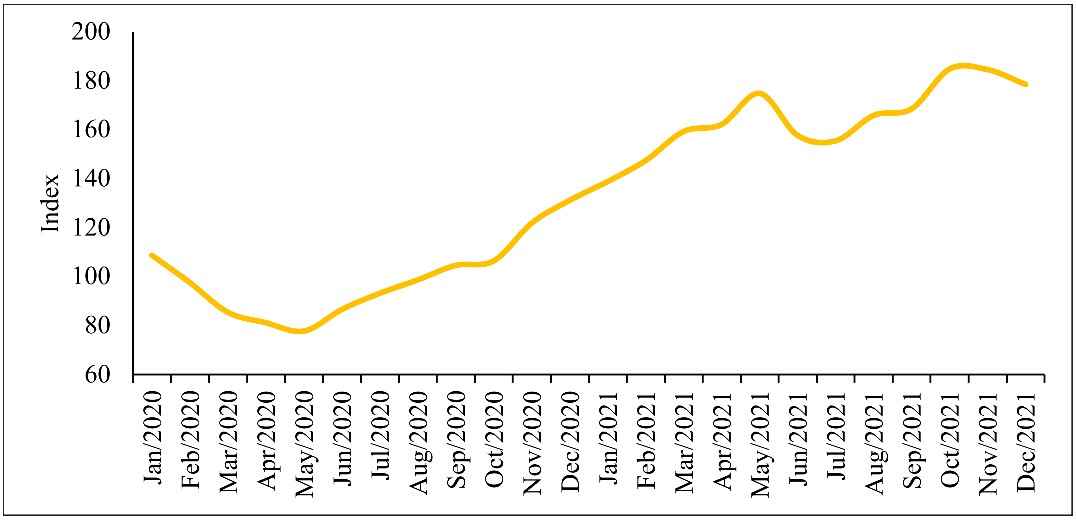

स्रोतः एफएओ

5.17 अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के साथ खाद्य तेलों के आयात में गिरावट आई। तेल वर्ष 2020-21 (नवंबर 2020-अक्टूबर 2021) के दौरान, भारत का खाद्य तेलों का आयात पिछले छह वर्षों में सबसे कम रहा है (चित्र 11)। हालांकि, मूल्य/वैल्यू के मामले में, खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को दर्शाते हुए, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में इसमें 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 11: खाद्य तेलों का आयात

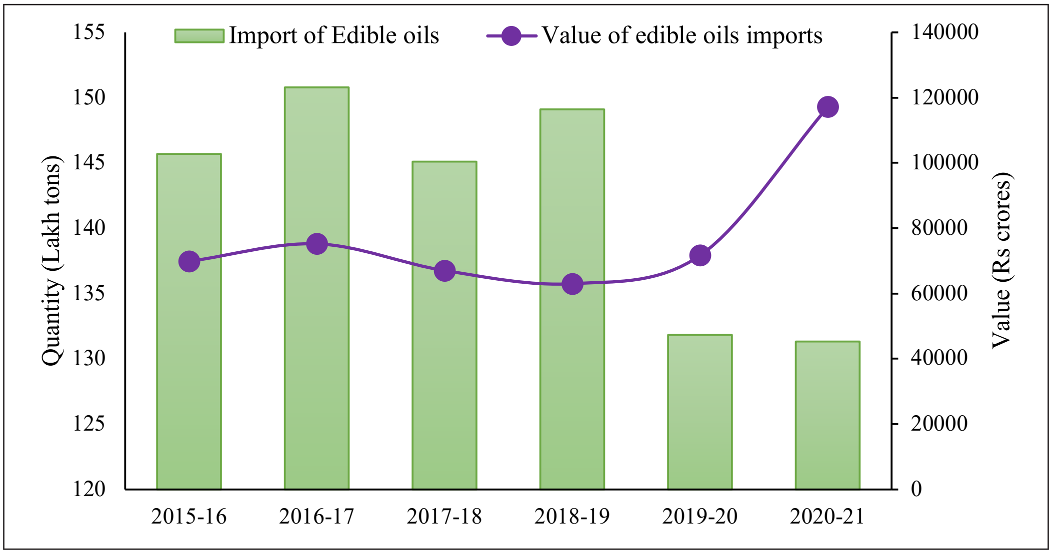

स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

5.18 दालों में मुद्रास्फीति, जो कि वर्ष 2020-21 में 16.4 प्रतिशत दर्ज की गई, 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 7.1 प्रतिशत और दिसंबर 2021 में 2.4 प्रतिशत रह गई। कोविड्-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों और लॉकडाउन के दौरान परिवारों द्वारा दालों के भंडारण के परिणाम के रूप में आपूर्ति पक्ष व्यवधानों की वजह से वर्ष 2020 में मद्रास्फीती उच्च थी। प्रतिबंधों में ढील दिए जाने और खरीफ दलहनों के लिए बुवाई क्षेत्र में 142.4 लाख हेक्टेयर (1 अक्टूबर 2021 को) के एक नए उच्च स्तर पर वृद्धि के साथ, पिछले साल देखी गई उच्च कीमतों से प्रोत्साहन के साथ, दालों की मुद्रास्फीति अधोगामी/नीचे की ओर है (चित्र 12)।

चित्र 12: दालों और उत्पादों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति

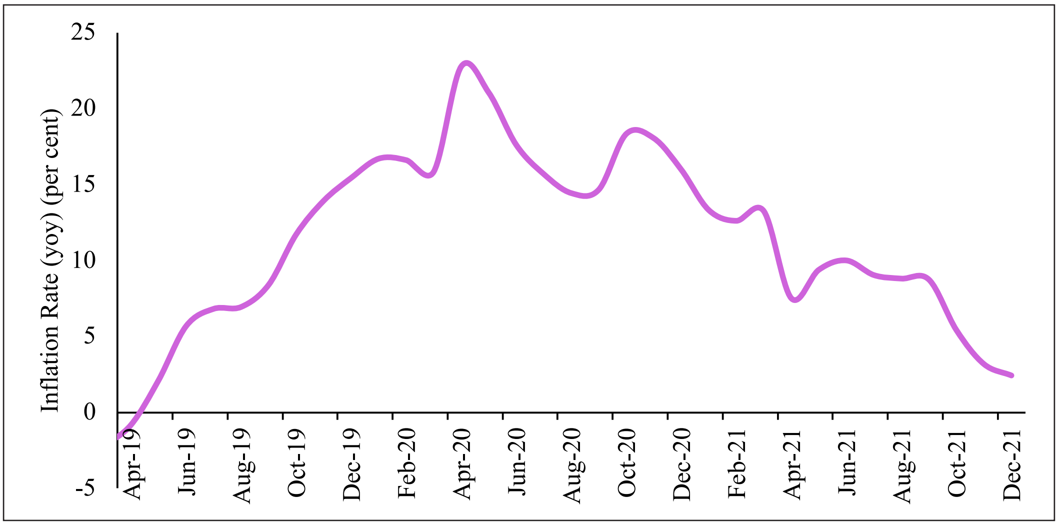

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

बॉक्स 2: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं:

दालें और प्याज

बफर बनाना

- बफर स्टॉक के उपयोग के माध्यम से मूल्य वृद्धि के दौरान प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसानों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से 2020-21 और 2021-22 में दालों की खरीद की है। 2021-22 में दाल बफर का लक्ष्य 23 एलएमटी है। 2021-22 में 2.08 एलएमटी का प्याज बफर बनाया गया है और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए एक कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया गया है।

आयात नीति

- दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 31 मार्च 2022 तक अरहर और उड़द को 'मुक्त' आयात श्रेणी में रखा गया है।
- मसूर पर मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को घटाकर क्रमश: शून्य और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 2.5 एलएमटी उड़द और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए म्यांमार के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और मलावी के साथ 0.50 एलएमटी तुअर के वार्षिक आयात के लिए समझौता किया गया है। 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए मोजाम्बिक के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खाद्य तेल

- खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी के लिए, 14 अक्टूबर 2021 से खाद्य तेल पर शुल्क कम कर दिया गया है।
- 14 अक्टूबर 2021 से खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी के लिए, रिफाइंड पाम तेल/पामोलिन, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अटकलें और जमाखोरी

- एनसीडीईएक्स पर सरसों के तेल में वायदा कारोबार को निलंबित कर दिया गया है और स्टॉक की सीमा लगा दी गई है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है। 8 अक्टूबर, 2021 से विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया गया है तथा स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2021 जारी किया गया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से घोषित किया जाता है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है।

उत्पादन और विकल्प

- सरकार आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए द्वितीयक खाद्य तेलों, विशेष रूप से चावल की भूसी के तेल के उत्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रही है।

सोयाबीन आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल

- 'सोया मील' की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। सोया मील पर स्टॉक की सीमा 23 दिसंबर, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए लगाई गई है।

जल्द खराब होने वाली (संवेदनशील) आवश्यक वस्तुएं

- जल्द खराब होने वाली/संवेदनशील वस्तुओं के लिए, नवंबर 2018 में ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को बाद में टीओपी/टॉप (टमाटर, प्याज, आलू) से बढ़ाकर टोटल/टीओटीएएल (41 खराब होने वाली वस्तुओं) तक विस्तारित कर दिया गया है। योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पादन समूहों और सम्मिलित किए गए लाभार्थियों के संदर्भ में व्यापक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में, 52 उत्पादन समूहों से 41 खराब होने वाली/संवेदनशील वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। प्रारंभ से 15.12.2021 तक, अब तक 3.05 लाख मीट्रिक टन टीओपी फसलों के परिवहन/भंडारण के लिए सब्सिडी के रूप में 65.79 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप टीओपी के अलावा 51.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ 2.82 लाख मीट्रिक टन फसलों का अतिरिक्त परिवहन/भंडारण हुआ है।

- उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम करने के लिए किसान रेल ट्रेनों की शुरुआत की गई। 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल सेवा शुरू होने और 14 जनवरी 2022 तक, भारतीय रेलवे ने फलों और सब्जियों सहित लगभग 6.23 लाख टन शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को ढ़ोते हुए 1,900 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है।

बॉक्स 3: तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी के तेल (केरोसिन ऑयल) की कीमतों का रुझान

एलपीजी/घरेलू गैस

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी होती हैं। देश में एलपीजी की कीमतें सऊदी संविदा मूल्य (सीपी) पर आधारित हैं, जो एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के लिए बेंचमार्क/मानदंड है। सऊदी सीपी अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2021 (236 अमरीकी डालर से 846 अमरीकी डालर) तक लगभग 258 प्रतिशत बढ़ गया है।

एलपीजी सब्सिडी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजना के तहत संचालित होती है, जिसमें घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के रुझान की दिशा के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। मई, 2020 से घरेलू एलपीजी (दिल्ली मार्केट में) पर उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। हालांकि, दूर-दराज के क्षेत्रों और कुछ अन्य बाजारों में, कुछ सब्सिडी है जो मुख्य रूप से बंदरगाह से बॉटलिंग प्लांट तक उच्च अंतर्देशीय माल ढुलाई के कारण एक बाजार से दूसरे बाजार में भिन्न होती है।

गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करने के लिए, सरकार ने मई, 2016 में 5 करोड़ जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए ''प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) योजना शुरू की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया था। स्कीम के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से 7 माह पूर्व सितम्बर, 2019 में प्राप्त कर लिया गया। 01.04.2016 को पीएमयूवाई के कार्यान्वयन ने राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज को 61.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 01.04.2021 को 99.8 प्रतिशत करने में प्रमुख योगदान दिया। इसके अलावा, 1 फरवरी, 2021 को बजट स्पीच में, उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने की घोषणा की गई थी। अपने संशोधित संस्करण में, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना को अगस्त 2021 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उज्जवला 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें लाभार्थियों की सभी मौजूदा पात्र श्रेणियों को शामिल किया गया है। उज्ज्वला 2.0 उन प्रवासियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करती है जो निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) के रुप में एक साधारण स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि प्रवासियों को निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) की व्यवस्था करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही उज्ज्वला 2.0 के सभी लाभार्थियों को मुफ्त फर्स्ट रिफिल और स्टोव प्रदान किया जा रहा है। 31.12.2021 तक, उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत प्रवासियों के लिए 2.2 लाख सहित कुल 96 लाख जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

मिटटी का तेल/केरोसिन

मिट्टी के तेल का उपयोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से प्रकाश और खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता रहा है। सरकार ने प्रकाश की जरूरतों के लिए बिजली की बढ़ती कवरेज और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग को देखते हुए खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजलीघर योजना) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद मिट्टी के तेल का उपयोग लगातार कम हो रहा है।

37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 11राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों[2] केरोसिन मुक्त हैं अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) द्वारा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई पीडीएस केरोसिन आवंटित नहीं किया गया है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को त्रैमासिक आधार पर एमओपी एंड एनजी द्वारा पीडीएस केरोसिन आवंटित किया जाता है। केरोसिन पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाता है और शून्य केंद्रीय सब्सिडी के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। एलपीजी पेनिट्रेशन, पीडीएस केरोसिन की नॉन-लिफ्टिंग आदि, सरेंडर/कमी के लिए स्वैच्छिक अनुरोध आदि जैसे कारकों के आधार पर आवंटन अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है। तमिलनाडु राज्य सरकार अभी भी राज्य सब्सिडी के माध्यम से मिट्टी के तेल पर सब्सिडी दे रही है।

1 मार्च, 2020 से प्रभावी, पीडीएस केरोसिन का खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारतीय आधार पर शून्य अंडर-रिकवरी स्तर पर स्थिर रखा जा रहा है और राज्यों को बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

चित्र 18: पीडीएसकेरोसिन की कीमतें/दरें

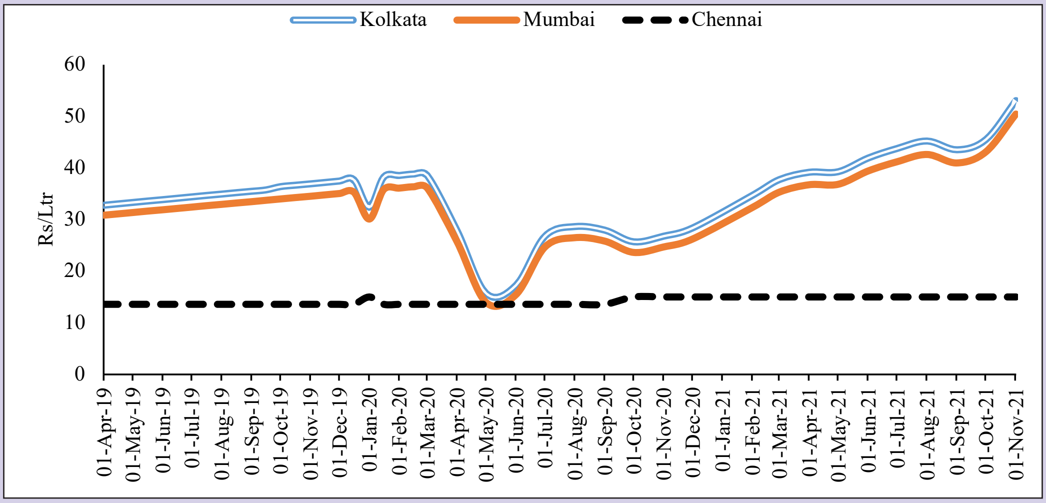

स्रोत: एमओपीएनजी

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर

5.19 जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक ग्रामीण और शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच बड़ा अंतर मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति की दरों में अतंर के कारण था। हालांकि, 2020 में अंतर कम हो गया (चित्र 13)। 2020 में, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के आस-पास/समान ही रही।

5.20 हम दो मुख्य विचलन बिंदुओं - नवंबर 2020 से मार्च 2021, और सितंबर 2021 से आगे का निरीक्षण करते हैं। विचलन पैटर्न में प्रमुख कारक 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह बन गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि सीपीआई ग्रामीण और शहरी दोनों में 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह को अधिक महत्व दिया गया है (चित्र 14)। ग्रामीण क्षेत्रों में 'ईंधन और प्रकाश' की मुद्रास्फीति मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में अलग-अलग ईंधन खपत पैटर्न के कारण शहरी क्षेत्रों से अलग रही है। हालांकि, यह मुख्य रूप से समग्र सूचकांक में कम भार के कारण सीपीआई-ग्रामीण और सीपीआई-शहरी के विचलन पैटर्न में प्रमुख कारक के रूप में नहीं उभरता है।

[2]आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

चित्र 13: सीपीआई ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

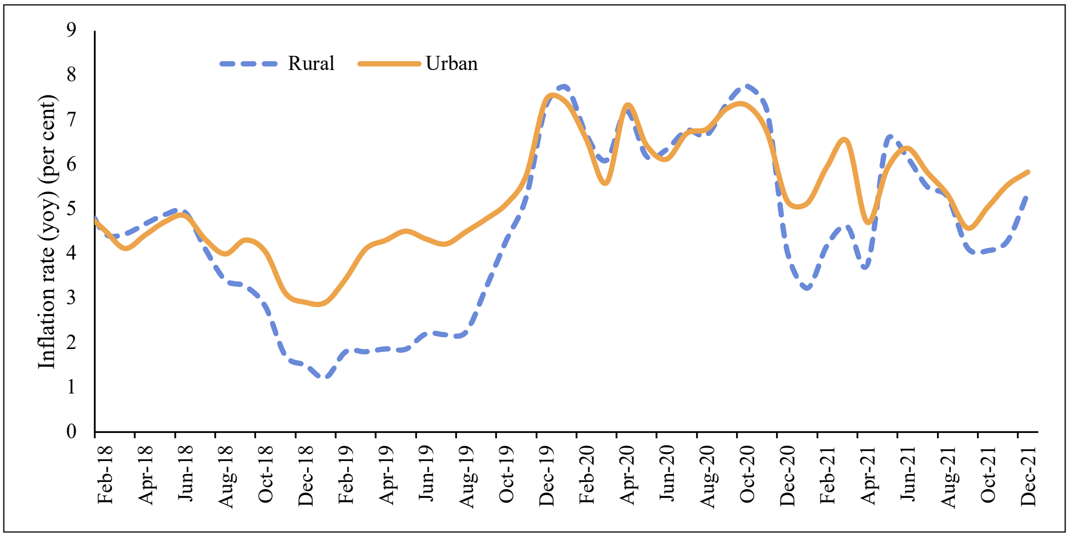

स्रोतः एनएसओ, एमओएसपीआई

चित्र 14: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'खाद्य और पेय पदार्थ' मुद्रास्फीति

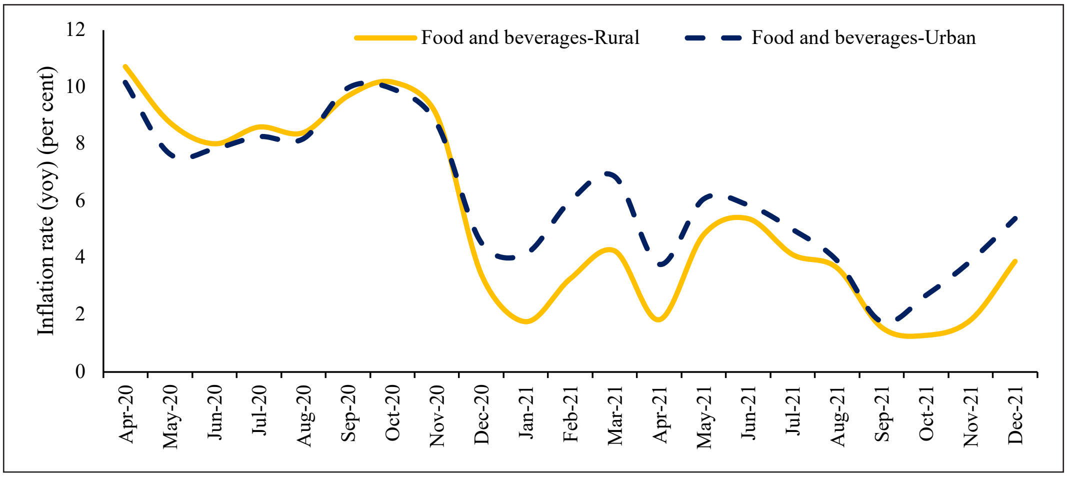

स्रोतः एनएसओ, एमओएसपीआई

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में रुझान/प्रवृत्तियाँ

5.21 चालू वित्त वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में देखे गए रुझानों के विपरीत, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई है और यह उच्च बनी हुई है (चित्र 15)। थोक मुद्रास्फीति 2020-21 और 2019-20 के दौरान अनुकूल/सौम्य रही है जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में मध्यम या निम्न रही है। इसलिए, वर्तमान में देखी जा रही उच्च मुद्रास्फीति का एक हिस्सा पिछले वर्ष में निम्न आधार की वजह से हो सकता है।

5.22 हालांकि सभी तीन प्रमुख समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अधिक रही है, यह 'ईंधन और बिजली' समूह में 20 प्रतिशत से ऊपर थी, जो कि उच्च अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों को दर्शाता है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था (तालिका 3)। प्राथमिक वस्तु समूह के भीतर, 'कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस' उप-समूह में बहुत अधिक मुद्रास्फीति देखी गई है और दिसंबर 2021 में यह 55.7 प्रतिशत पर था। इसी तरह, खनिजों में पूरे वर्ष उच्च मुद्रास्फीति देखी गई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का प्रभाव विशेष रूप से बुनियादी

धातुओं के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था (बॉक्स 4)। बुनियादी धातुओं के निर्माण में 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 27.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई। विनिर्मित खाद्य उत्पादों में, खाद्य तेलों का प्रमुख योगदान था। 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान डबल्यूपीआईमें खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति 36.4 प्रतिशत थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खाद्य तेलों पर उच्च आयात निर्भरता का मतलब है कि इन उत्पादों में उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित होती हैं। इस अवधि के दौरान वस्त्र निर्माण में मुद्रास्फीति भी 15.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही, जो कपड़ा रेशों/टेक्सटाइल फाइबर की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी।

चित्र 15: डबल्यूपीआई में रुझान - समस्त पण्य, खाद्य और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति

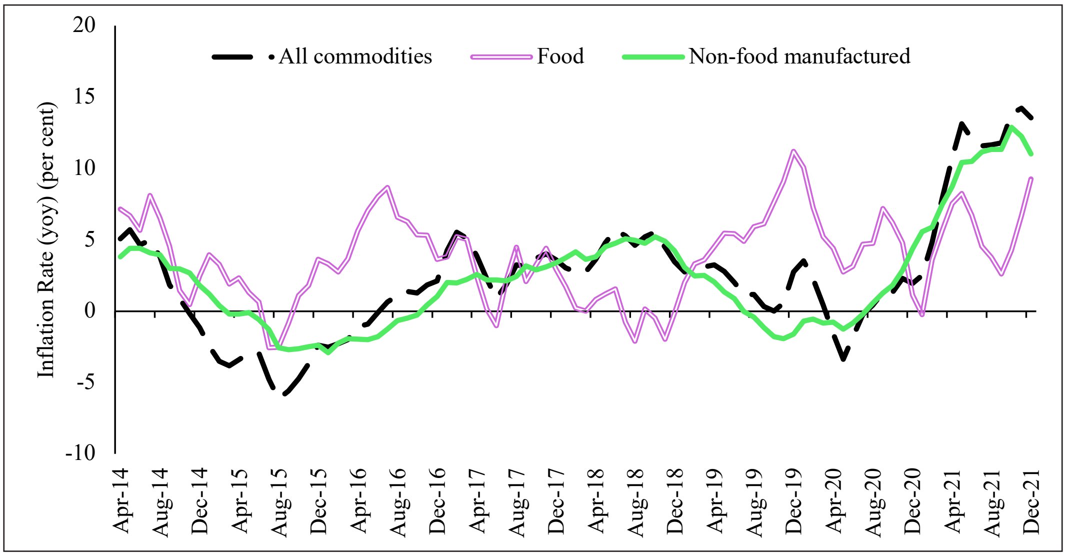

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

तालिका 3: डबल्यूपीआई-आधार 2011-12 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	भार/वजन	2019-20	2020-21	2020-21^	2021-22#	अप्रैल-21	मई-21	जून-21	जुलाई-21	अगस्त-21	सितंबर-21	अक्तूबर-21	नवंबर-21(पी)	दिसंबर-21(पी)
सभी कमोडिटी	100	1.7	1.3	0.0	12.5	10.7	13.1	12.1	11.6	11.6	11.8	13.8	14.2	13.6
प्राथमिक वस्तुएँ	22.6	6.8	1.7	1.3	8.6	9.9	9.4	8.6	6.3	5.9	6.0	7.4	10.3	13.4
खाद्य पदार्थ	15.3	8.4	3.2	4.0	2.5	4.6	4.2	3.3	0.1	-0.8	-2.6	1.0	4.9	9.6
अनाज	2.8	7.5	-2.6	-1.4	1.6	-3.1	-2.6	-2.8	-2.9	-1.1	1.3	3.2	4.0	5.1
दालें	0.6	15.9	11.6	12.1	8.1	10.7	12.1	11.6	8.4	9.5	9.3	5.0	2.9	3.9
सब्जियाँ	1.9	31.1	3.4	7.6	-6.6	-9.0	-7.2	-0.8	-8.3	-12.6	-32.3	-17.4	3.9	31.6
गैर-खाद्य पदार्थ	4.1	4.6	1.3	-0.4	20.4	15.6	18.4	18.6	22.9	28.7	29.5	18.4	13.8	19.0
खनिज पदार्थ	0.8	13.2	6.8	3.5	15.3	20.6	13.3	15.3	12.6	7.2	30.8	16.6	20.9	3.8
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2.4	-7.6	-17.4	-25.2	57.9	80.8	59.5	47.0	42.3	34.5	49.0	86.4	76.6	55.7
ईंधन और पावर	13.2	-1.8	-8.0	-11.6	31.4	21.3	36.7	29.3	27.0	28.2	29.5	38.6	39.8	32.3
विनिर्मित उत्पाद	64.2	0.3	2.8	1.5	11.3	9.4	11.3	11.0	11.5	11.6	11.6	12.9	11.9	10.6
खाद्य पदार्थ	9.1	4.1	5.6	5.0	12.5	13.1	15.6	13.3	13.1	12.7	12.9	12.8	10.3	8.7
खाद्य तेल	2.6	1.5	20.3	17.5	36.4	44.5	51.9	43.6	42.7	40.7	37.4	33.2	23.2	16.8
खाद्य सूचकांक	24.4	6.9	4.0	4.3	5.9	7.5	8.2	6.7	4.5	3.8	2.6	4.3	6.7	9.2
गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	-0.4	2.2	0.8	11.1	8.7	10.4	10.5	11.1	11.3	11.3	12.9	12.3	11.0

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी पी: अनंतिम

^: अप्रैल से दिसंबर 2020; #: अप्रैल से दिसंबर 2021

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन

5.23 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-सी पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर में जून 2019 से विचलन दर्ज किया गया है। जून 2019 से फरवरी 2021 के बीच थोक महंगाई खुदरा महंगाई से कम रही, जबकि मार्च 2021 से दिसंबर 2021 के बीच थोक महंगाई खुदरा महंगाई से ऊपर रही। चालू वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सीपीआई से अधिक थी लेकिन विचलन भी बढ़ा (चित्र 16)। दिसंबर 2021 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर खुदरा मुद्रास्फीति की तुलना में 8 प्रतिशत अंक अधिक थी। यह प्रवृत्ति संभावित प्रश्न उठाती है: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति, सीपीआई मुद्रास्फीति से अधिक होने के बावजूद सीपीआई मुद्रास्फीति, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से अलग क्यों हो रही है?

5.24 कोविड़-19 महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, उत्पादन गतिविधि 2020-21 में मंदित रही और मांग में कमी के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। इसलिए, 2020-21 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर 1.3 प्रतिशत के निचले स्तर को छू गई। 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, 2020-21 के निम्न आधार के कारण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 14.2 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 12.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। (अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 0.04 प्रतिशत के मुकाबले)। इसलिए, 2021 में उच्च डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर काफी हद तक पिछले वर्ष के निम्न आधार के कारण है। दूसरी ओर, खुदरा मुद्रास्फीति जो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 2020-21 के दौरान उच्च बनी हुई थी, प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के कारण 2021-22 में कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के बीच विचलन हुआ।

चित्र 16: सी पी आई और डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति के बीच अंतर

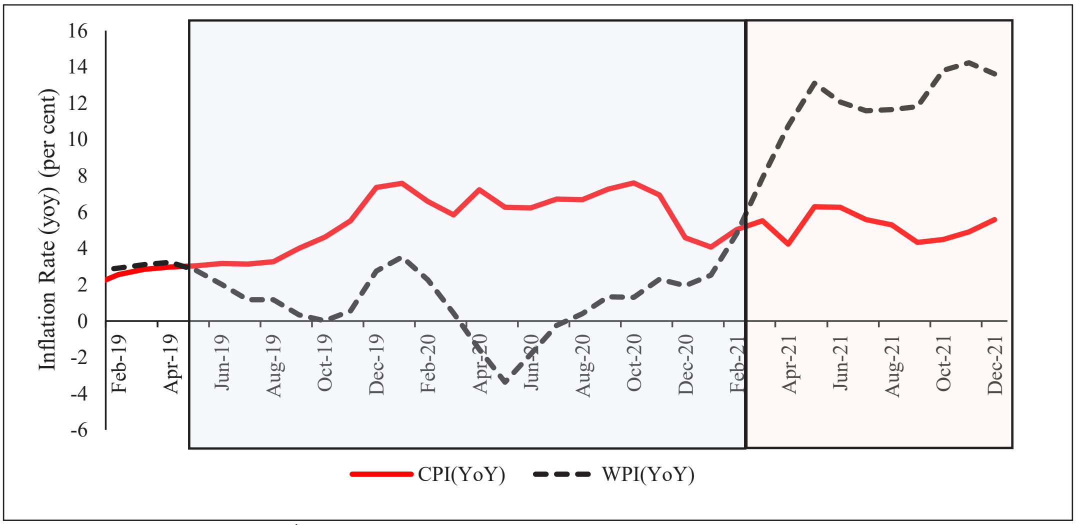

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआईऔर ओईए, डीपीआईआईटी

5.25 हालांकि डबल्यूपीआई और सीपीआई में विचलन के कारणों में से एक कारण आधार प्रभाव भी हो सकता है, दो सूचकांकों में वर्तमान विचलन को उनके उद्देश्य और डिजाइन में अंतर और दोनों के विभिन्न घटकों के मूल्य व्यवहार के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। सीपीआई उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार को दर्शाता है, जो एनएसएस घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए घरेलू खपत पैटर्न के आधार पर प्राप्त होता है, और खुदरा स्तर पर मूल्य उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। दूसरी ओर, डबल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर बिक्री के पहले बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक लेनदेन में संबंधित वस्तुओं की हिस्सेदारी पर आधारित है। इसलिए, हालांकि सीपीआई-सी में वस्तुओं का भार उपभोक्ताओं और घरों के उपभोग पैटर्न पर आधारित होता है,

डब्ल्यूपीआई श्रृंखला के मामले में, आइटम बास्केट के वजन को घरेलू उत्पादन में शुद्ध व्यापार मूल्य की गणना करके घरेलू उत्पादनमें शुद्ध आयात को जोड़कर निकाला जाता है।

5.26 विशिष्ट वस्तु समूहों के महत्व और मान/वजन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। सीपीआई में, खाद्य और पेय पदार्थों का वजन सबसे अधिक (45.9) होता है, डब्ल्यूपीआई में, विनिर्मित समूह का वजन सबसे अधिक (64.2) होता है। ईंधन समूह का भार थोक मूल्य सूचकांक (13.2) की तुलना में सीपीआई (6.8) में काफी कम है। सीपीआई में ईंधन भी आंशिक रूप से 'परिवहन और संचार' के तहत विविध समूह के तहत परिलक्षित होता है। सीपीआई में विविध समूह, में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सोने के आभूषण जैसे सामान शामिल हैं जो सूचकांक (28.3) का लगभग एक चौथाई बनाता है। डबल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं हैं।

5.27 आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण 2020 के दौरान खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई। चूंकि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम किया गया और विशेष रूप से दालों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं के लिए प्रभावी आपूर्ति पक्ष उपाय किए गए, जिनके लिए आयात अधिक रहा है। 2021 में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई और दिसंबर 2021 में 4.0 प्रतिशत थी। औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.1 प्रतिशत थी। सीपीआई में 45.9 के वजन के मुकाबले, डब्ल्यूपीआई में खाद्य वस्तुओं का वजन केवल 24.4 है (प्राथमिक समूह के साथ साथनिर्मित समूह में आने वाले में खाद्य पदार्थ)। सीपीआई में भोजन का उच्च भार सीपीआई को डब्ल्यूपीआई की तुलना में खाद्य कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

5.28 जैसा कि ऊपर कहा गया है, डब्ल्यूपीआई निर्मित उत्पादों और 'ईंधन और बिजली' समूह को एक बड़ा भार/मान प्रदान करता है। महामारी के कारण लंबे समय तक देश भर में औद्योगिक गतिविधियों के बंद रहने के कारण, ऊर्जा और इनपुट की मांग में तेज गिरावट देखी गई और इससे विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट आई। हालांकि, दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के साथ, ऊर्जा की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और औद्योगिक इनपुट लागत दबाव और उच्च माल ढुलाई लागत के कारण 2021 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में भी तेज वृद्धि हुई। यह वर्ष के दौरान निर्मित क्षेत्र और ईंधन समूह में उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में परिलक्षित हुआ। इस प्रकार, जहां एक ओर कम खाद्य मुद्रास्फीति ने सीपीआई को नीचे खींच लिया, वहीं दूसरी ओर उच्च ऊर्जा और इनपुट कीमतों ने डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर (चित्र 17) को बढ़ा दिया।

चित्र 17: खुदरा खाद्य और थोक ऊर्जा कीमतों में सालाना मुद्रास्फीति चक्र

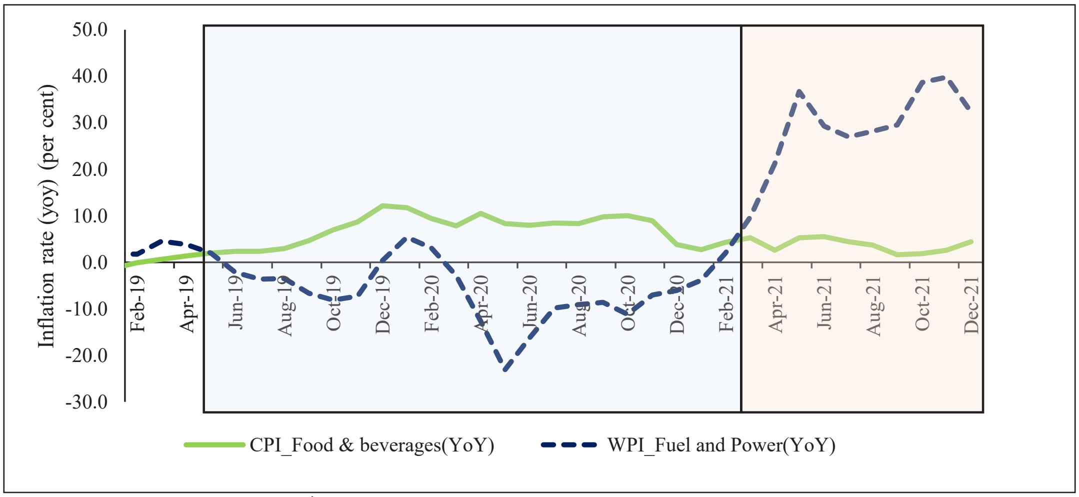

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

5.29 विनिर्माण क्षेत्र न केवल कच्चे तेल का उपयोग करता है बल्कि लौह अयस्क, एल्यूमीनियम, अन्य धातु और कपास जैसी कई अन्य आयातित मदों का भी इनपुट के रूप में उपयोग करता है। डब्ल्यूपीआई के ऐसे मध्यवर्ती और इनपुट मद जो कि सीपीआई का हिस्सा नहीं हैं सीपीआई से इसके विचलन में एक भूमिका निभाते हैं। ऐसी विभिन्न इनपुट मदों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, जिनका आयात हिस्सा अधिक है, डब्ल्यूपीआई (बॉक्स 4) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, न कि सीपीआई को।

5.30 हालांकि सीपीआई उपसमूह 'परिवहन और संचार' जिसमें वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल शामिल है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, डब्ल्यूपीआई का उप-समूह 'ईंधन और बिजली', जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है, बहुत अस्थिर रहा है (चित्र 18)। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में ईंधन समूह का योगदान सीपीआई में उपसमूह 'परिवहन और संचार' की तुलना में सूचकांक में उनके उच्च भार के कारण अधिक था। (चित्र 18)

चित्र 18: खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन

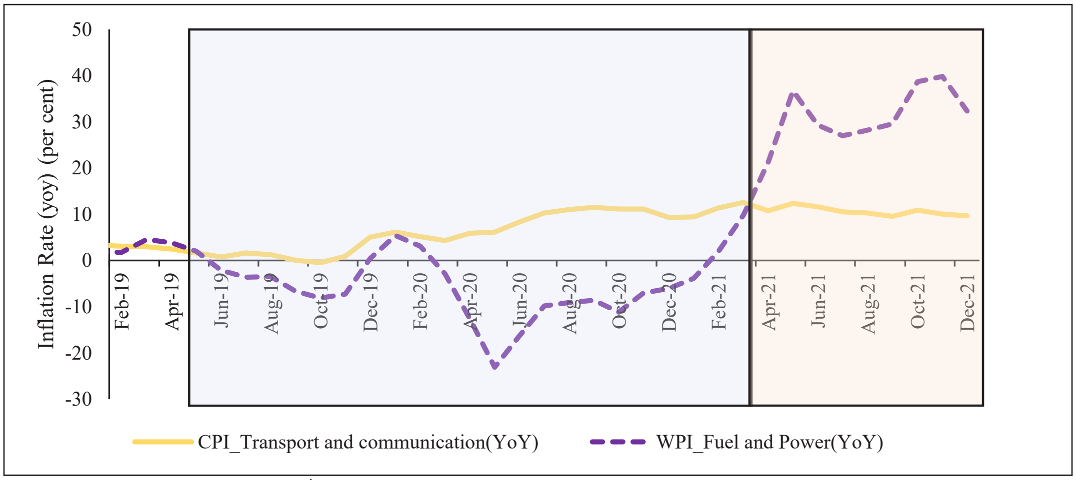

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

5.31 2020 में कच्चे तेल की मांग में गिरावट के कारण वर्ष पेट्रोल और डीजल की थोक कीमतों में गिरावट ने (इसमें कर और शुल्क शामिल नहीं हैं), 2021 के दौरान थोक मुद्रास्फीति के लिए निम्न आधार बनाया, जबकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा मुद्रास्फीति कर तथा शुल्क से प्रभावित हुई। यह उत्पाद शुल्क जो अन्य स्रोतों से राजस्व कम होने के कारण लगाए गए थे, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण कम हो गए। 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने लगी। नवंबर 2021 में डीजल और पेट्रोल के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में इस कटौती और बाद में अधिकांश राज्यों द्वारा वैट में कमी का डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ा, परंतु फिर भी थोक मूल्य उच्च स्तर पर ही बने रहे जिसके परिणामस्वरूप विचलन का विस्तार हुआ (चित्र 19 और 20)।

चित्र 19: पेट्रोल की खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर

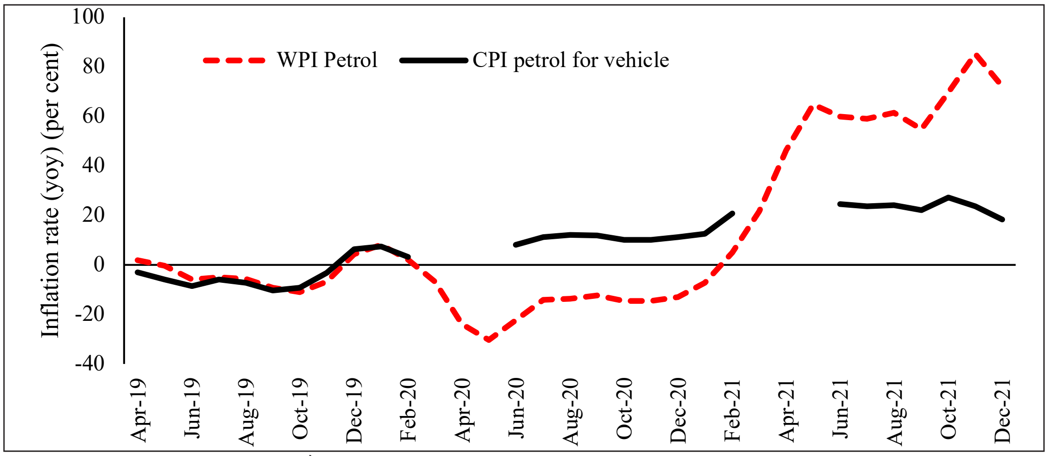

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: वाहन के लिए सीपीआई पेट्रोल का आइटम लेवल इंडेक्स मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं था।

चित्र 20 : डीजल की खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर

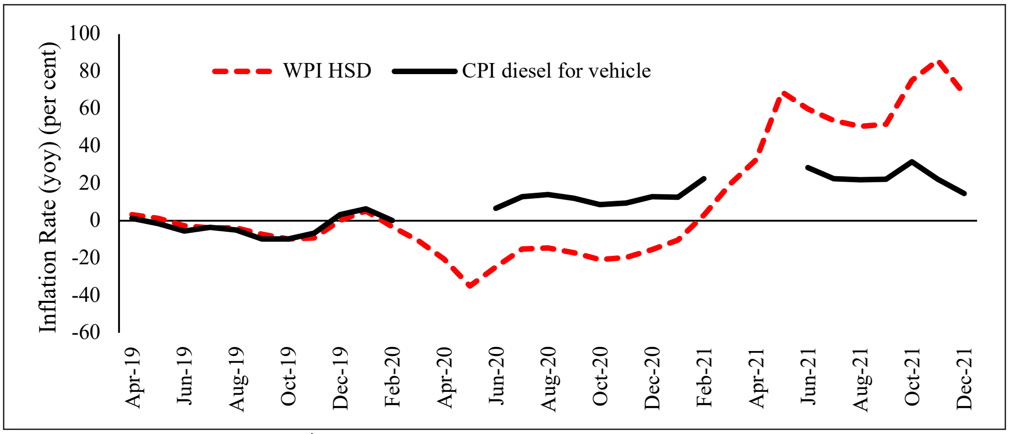

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: वाहन के लिए सीपीआई पेट्रोल का आइटम लेवल इंडेक्स मार्च-मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं था।

5.32 विचलन का एक अन्य कारण मांग में कमी होना है। हालांकि महामारी पूर्व स्तर तक पहुंचने के लिए 2021-22 में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा है, खपत की मांग अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। कमजोर हस्तांतरण होने के साथ, डबल्यूपीआई और सीपीआई के बीच का अंतर बढ़ रहा है लेकिन आधार प्रभाव के कमजोर होने के साथ इसके धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

बॉक्स 4: वैश्विक कमोडिटी की कीमतें और घरेलू मुद्रास्फीति

2020 और 2021 की दूसरी छमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक रहा है। कोविड-19 अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद, ऊर्जा सूचकांक ने जनवरी 2021 से 12 महीनों में से 5 में तीन अंकों की वृद्धि दर्ज की है (चित्र 4ए) । चालू वर्ष के दौरान खाद्य और धातु और खनिज कीमतों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

चित्र 4ए: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्य सूचकांकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

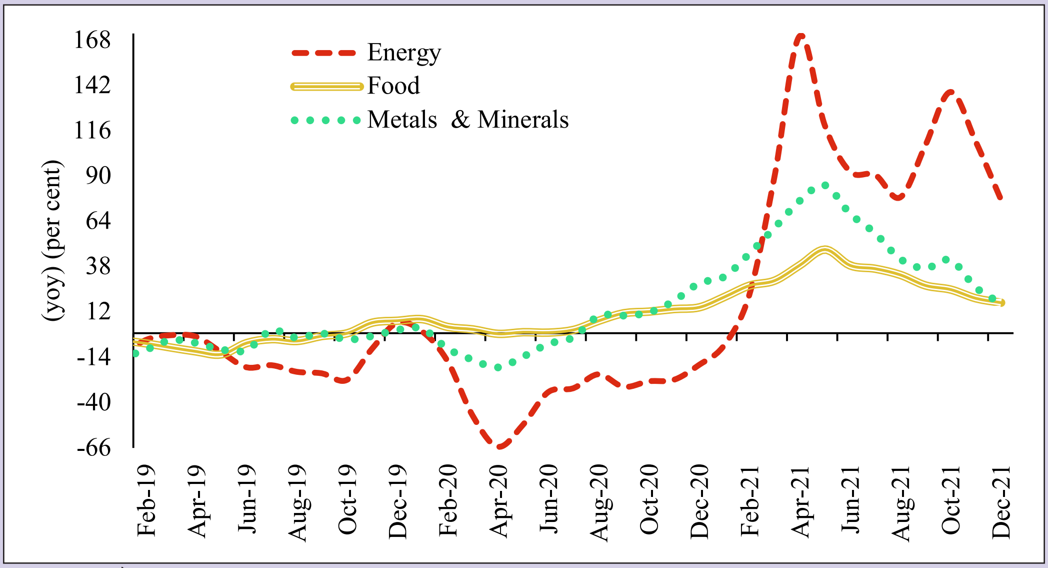

स्रोत: विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य सूचकांक

हालांकि भारत में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन के कारण नियंत्रण में रही, विनिर्माण वस्तुओं की उच्च वैश्विक कीमतों का घरेलू कीमतों, विशेष रूप से मूल धातुओं पर प्रभाव पड़ा है। वाहनों, विनिर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि और निर्माण गतिविधियों में तेजी के कारण वैश्विक एल्युमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते एल्युमीनियम के एक प्रमुख निर्यातक चीन ने अपने उत्पादन में कटौती की है।

तांबे की कीमतों में 2021 के शुरुआती महीनों में वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं में असाधारण वैश्विक उठाव और चीन से बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में अपने बढ़े हुए निवेश के कारण मांग की वजह से भी है। कम होती मांग और चिली और पेरू में स्ट्राइक के खतरों ने उत्पादन जोखिम बढ़ा दिया है और तांबे की कीमतों पर दबाव बनाया है (विश्व बैंक, 2021)।

लौह अयस्क की कीमतों में शुरुआती उछाल काफी हद तक चीन में इस्पात उत्पादन की मजबूत मांग को दर्शाता है, जिससे लौह अयस्क के आयात में वृद्धि हुई है। हालांकि, हाल ही में कीमतों में गिरावट देखी गई है। शीर्ष निर्यातक ऑस्ट्रेलिया में पहले के मौसम की गड़बड़ी और नंबर दो शिपर ब्राजील[3] में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद हाल के महीनों में लौह अयस्क की आपूर्ति में सुधार हुआ है।

[3]https://www.reuters.com/world/americas/iron-ore-makes-unruly-retreat-more-normal-price-levels-russell-2021-09-20/

पहली तिमाही में टिन की कीमतों में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जो मार्च 2021 में 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में टिन सोल्डर की बढ़ती मांग के साथ-साथ बोलीविया, पेरू और मलेशिया में लॉकडाउन, ब्राजील और इंडोनेशिया में स्वैच्छिक उत्पादन में कटौती और म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आपूर्ति में व्यवधान से कीमतों में वृद्धि हुई (विश्व बैंक, 2021क)।

मई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतें ऊपर की ओर रुझान दिखा रही हैं और पिछले दस वर्षों में देखी गई तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। कपास सूचकांक की कीमत जो अप्रैल 2020 में 1.40 डॉलर प्रति किलोग्राम थी, नवंबर 2021 में तेजी से बढ़कर 2.79 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई, हालांकि दिसंबर 2021 में यह घटकर 2.65 डॉलर प्रति किलोग्राम रह गया है। कपास की कीमतों में मजबूती की वजह, वर्ष 2020 में कोविड़-19 संबंधित संकुचन के बाद कपास की मांग में सुधार मानी जा सकती है (विश्व बैंक, 2021ख)।

संबंधित वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापी गई घरेलू मुद्रास्फीति इन वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के साथ अत्यधिक सह-संबधित रही है। घरेलू एल्युमीनियम और तांबे की कीमतों में मुद्रास्फीति सकारात्मक है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है (चित्र 4बी)।

चित्र 4बी: एल्युमीनियम, कॉपर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति और संबंधित वस्तुओं में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (जनवरी 2018-दिसंबर 2021)

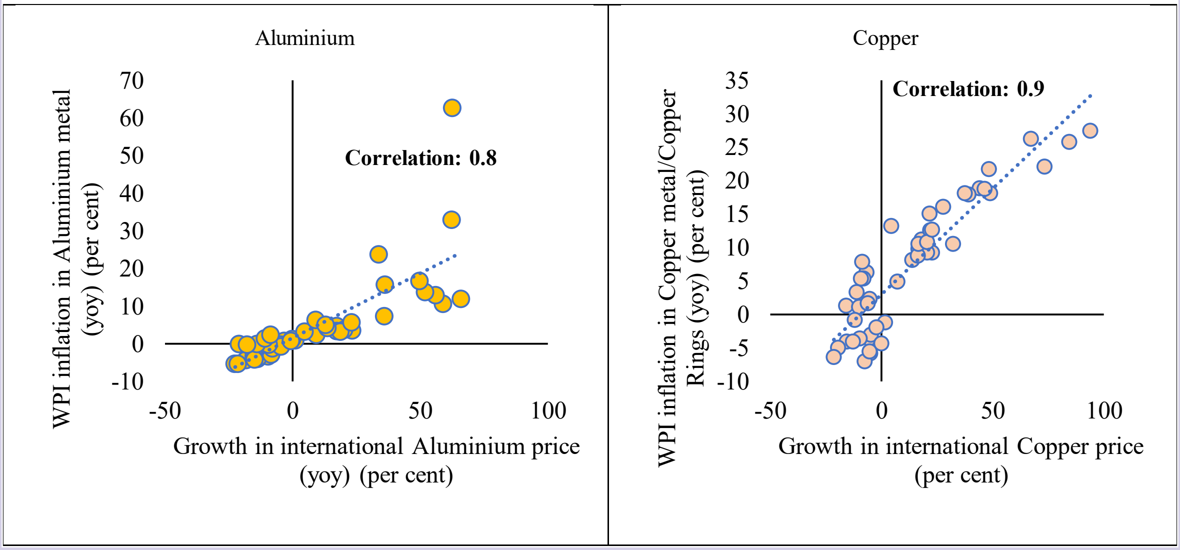

स्रोतः विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत अपने कच्चे तेल की खपत का सबसे ज्यादा आयात करता है। जैसा कि अपेक्षित था, घरेलू कच्चे तेल बास्केट की कीमतें विशेष रूप से भारतीय कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित हैं (चित्र 29)। कच्चे तेल में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत में साल-दर-साल वृद्धि के साथ 0.98 का सहसंबंध है।

चित्र 4सी: कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति और कच्चे पेट्रोलियम में डबल्यूपीओआई मुद्रास्फीति (जनवरी 2018-दिसंबर 2021)

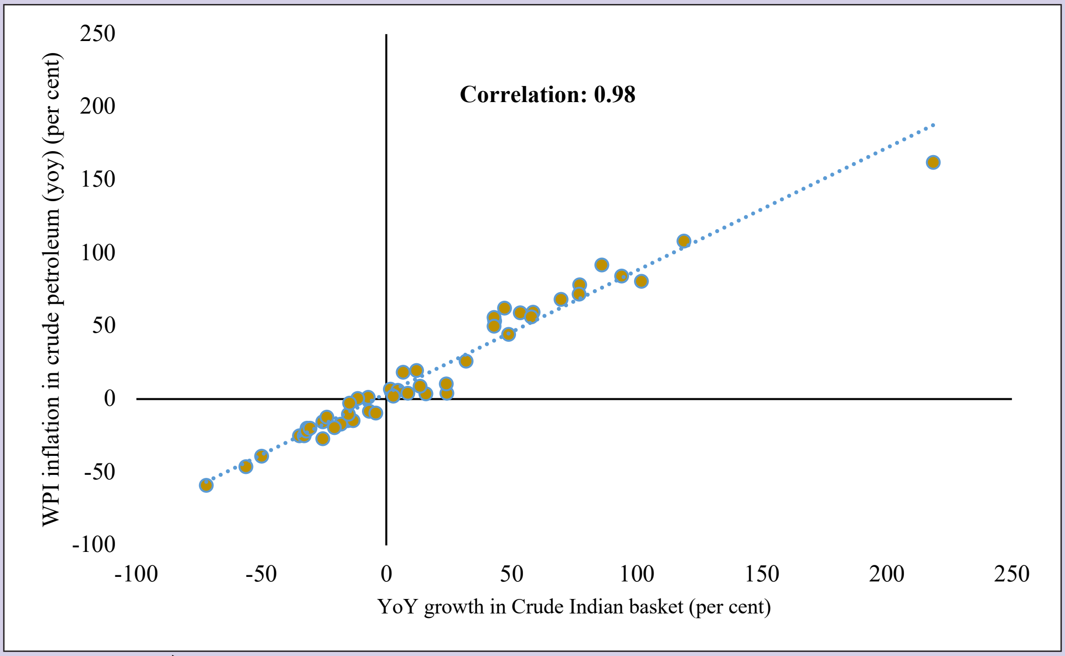

स्रोत: पीपीएसी और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का पर्याप्त हिस्सा भी आयात करता है। पामऑइल /ताड़ के तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कोई भी बदलाव घरेलू कीमतों में भी संचारित हो जाता है क्योंकि उनका सह संबंध लगभग 0.9 है। (चित्र 4डी)।

चित्र 4डी: पामऑइल/ताड़ के तेल में थोक मूल्य सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति (जनवरी 2018 - दिसंबर2021)

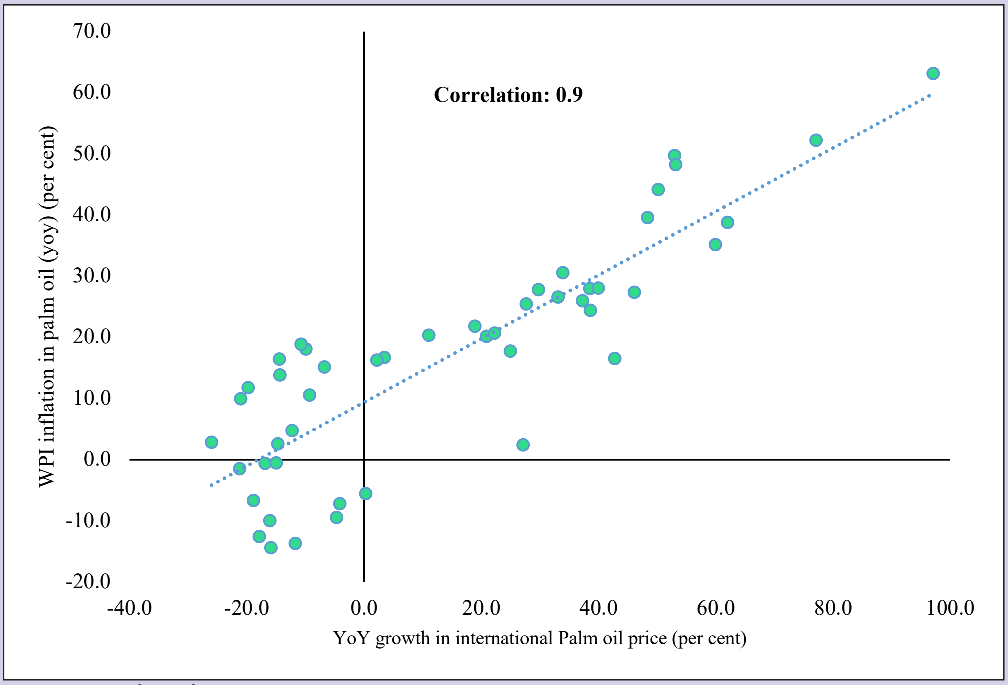

स्रोत: विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

भारत कपास का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसलिए, घरेलू कपास की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय कीमतें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों के रुझान को दर्शाता है। चित्र 4एफ सूती धागे/कॉटनयार्न में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और कच्चे कपास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के बीच उच्च सह संबंध (0.9) दर्शाता है ।

चित्र 4ई: अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य (एक सूचकांक)

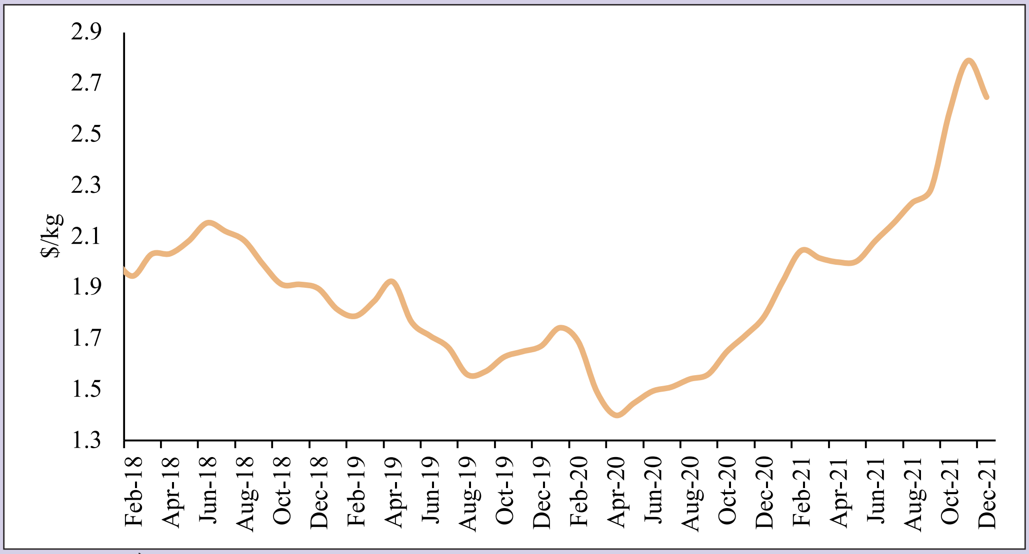

स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 4एफ: सूती धागे में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति और कपास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति (जनवरी 2018 - दिसंबर 2021)

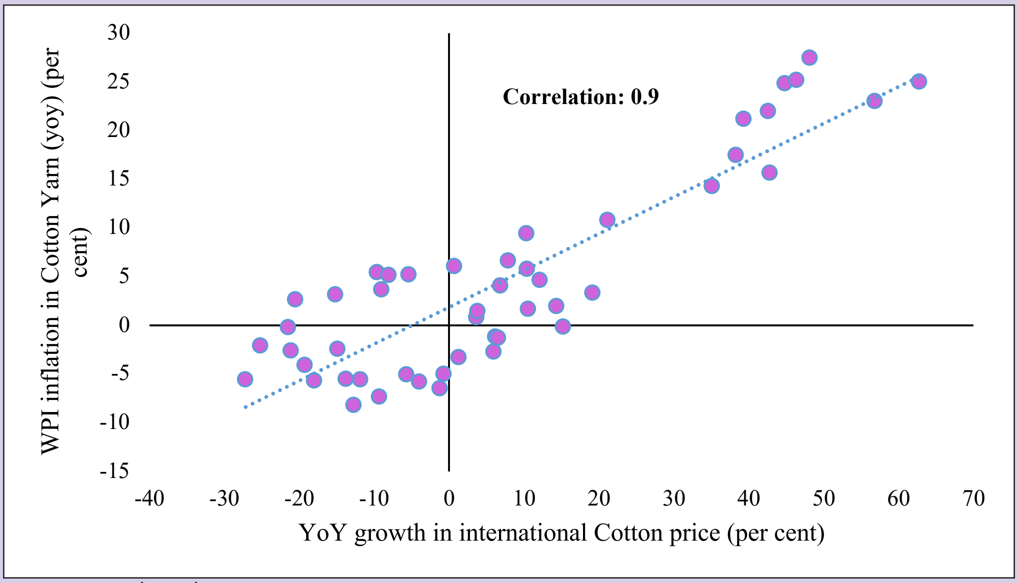

स्रोत: विश्व बैंक और ओईए, डीपीआईआईटी

इसलिए डबल्यूपीआई में निर्मित समूह में रिपोर्ट की गई उच्च मुद्रास्फीति दर आयातित इनपुट की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप ''आयातित मुद्रास्फीति'' के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उच्च माल ढुलाई लागत और लंबी डिलीवरी अवधि ने आयातित इनपुट पर कीमत के दबाव को और बढ़ा दिया।

आवास दरें

5.33 आवासन क्षेत्र/हाउसिंग सेक्टर भी कोविड्-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आपूर्ति और मांग दोनों चौनलों के माध्यम से प्रभावित था। प्रारंभिक कोविड् -19 प्रतिबंधों के बीच, न केवल नए घरों का निर्माण धीमा हुआ, बल्कि नई आवास परियोजनाओं के शुभारंभ में भी देरी हुई। आय में कमी, भविष्य की आय के बारे में अनिश्चितता और घर पर रहने के आदेश की वजह से घर खरीदारों ने अपनी खरीदारी में देरी की। प्रारंभिक कोविड् -19 प्रेरित प्रतिबंधों को हटा दिए जाने के बाद, आवास संपत्तियोंकी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ऐसा संभवतः महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों के जवाब में मांग और सामर्थ्य में सुधार जैसे कम ब्याज दरों, सर्कल दरों में कमी, और स्टांप शुल्क में कटौती, के कारण हुआ जिससे खरीदारों के लिए घर किफायती हो गए (बाक्स 5)। इसके अलावा, कई प्रमुख बैंकों, मोर्टगेज कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन पर अपनी ब्याज दरों में काफी कमी की है, जिससे आवास की मांग में सुधार हुआ है। दूसरी कोविड्-19 लहर (अप्रैल-जून, 2021) के दौरान, आवास संपत्तियों के लेन-देन पर एक बार फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन उतना नहीं जितना पहली कोविड्-19 लहर (अप्रैल-जून, 2020) के दौरान देखा गया था।

5.34 नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) रेजिडेक्स एचपीआई/असेसमेंट प्राइस इंडेक्स (बेस 2017-18) प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से लेनदेन के लिए आवासीय संपत्तियों की कीमतों को दर्ज करता है। 12 शहरों में आवासीय मकानों के लेनदेन और कीमतों पर पहली और दूसरी कोविड-19 लहर के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एनएचबी से प्राप्त मूल्यों और लेन-देन के रिकॉर्ड के समग्र सूचकांक संबंधी डेटा का उपयोग किया गया है।

बॉक्स 5: आवास की वहनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय

- आवास बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि जैसी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्किल दरों और स्टाम्प शुल्क में कमी।

कर लाभ

- किफायती आवास परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 तक कर छूट/रियायत।
- किफायती आवास के लिए 2019-20 के बजट में घोषित कर कटौती की पात्रता मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। यह कर कटौती 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है और यह स्व-अधिकृत मकान मालिकों के लिए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर प्रदान की जाएगी।

योजनाएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)

- पीएमएवाई-यू का उद्देश्य वर्ष-2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी

[4] एनएचबी रेजिडेक्स तिमाही आधार पर चुनिंदा शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है। अप्रैल-जून, 2018 तिमाही से आधार वर्ष को वित्त वर्ष 2017-18 में स्थानांतरित कर दिया गया है। संशोधित एनएचबी रेजिडेक्स अपने भौगोलिक कवरेज में व्यापक है और इसमें दो आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) सम्मिलित हैं जेसे 50 शहरो में /निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए एचपीआई आकलन मूल्य और एचपीआई बाजार मूल्य। वर्तमान डेटा स्रोत एचपीआई / आकलन कीमतों के लिए बैंकों और एचएफसी के मूल्यांकन डेटा और एचपीआई के लिए प्राथमिक और सेकेण्डरी बाजार डेटा हैं। निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए बाजार मूल्य। यह कवरेज भारत के 21 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां और 33 स्मार्ट शहर शामिल हैं। शहर के स्तर पर आवास की कीमतों को कारपेट एरिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मुख्यतः तीन तरह के उत्पाद होते हैं ढ=60 वर्गमीटर, झ60 और ढ=110 वर्ग मीटर, और झ 110 वर्ग मीटर। सूचकांकों की गणना लास्पेयर्स पद्धति का उपयोग करके की जाती है, इसके बाद उत्पाद श्रेणी स्तर पर गतिशील भार के अनुप्रयोग के साथ चार तिमाही भारित चलती औसत की गणना की जाती है और नए आधार वर्ष से शुरू होने वाली सभी तिमाहियों में भारित चलती औसत उत्पाद श्रेणी स्तर की कीमतों पर स्थिर आधार वर्ष भार होता है।

वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है।

- शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना के रूप में किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एएचआरसी)। मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 वर्षों के लिए रियायत करार-समझौतों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित किया जाएगा। रियायत ग्राही परिसरों को मरम्मत/रिट्रोफिट और कमरों के रखरखाव और पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि जैसे बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने के द्वारा रहने योग्य बना देगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पारदर्शी बोली के माध्यम से छूट ग्राही का चयन करेंगे। 25 साल बाद कॉम्प्लेक्स शहरी स्थानीय निकायों में वापस आ जाएंगे ताकि अगले चक्र को पहले की तरह फिर से शुरू किया जा सके या अपने आप चलाया जा सके। इसके अलावा, विशेष प्रोत्साहन जैसे उपयोग की अनुमति, 50 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)/फ्लोरस्पेस इंडेक्स (एफएसआई), प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार दर पर रियायती ऋण, किफायती आवास के बराबर कर राहत आदि की पेशकश की जाएगी। सार्वजनिक संस्थाएं 25 वर्षों के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी विकसित करेंगी।

मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिटलिंक्ड सब्सिडी योजना

- मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिटलिंक्डसब्सिडी योजना (6-18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय) जनवरी 2017 से लागू की जा रही है, जिसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है ताकि आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के लक्षित निवेश वाले 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को मई 2020 में घोषित किए गए आत्म निर्भर कार्यक्रम के तहतलाभ मिल सके। इससे स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने की भी उम्मीद थी।

5.35 यह मोटे तौर पर चित्र 21 क और 21 ख से देखा जा सकता है कि आवास की कीमतों की प्रतिक्रिया की तुलना में कोविड -19 शॉक के लिए आवास लेनदेन की प्रतिक्रिया बहुत अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि कीमतों की तुलना में आवासीय क्षेत्र में लगे झटके को लेनदेन में बदलाव के माध्यम से अधिक समायोजित किया गया। चूंकि मूल्य प्रतिक्रिया लेनदेन की प्रतिक्रिया से अपेक्षाकृत कम रहती है इसलिए आवासीय बाजार में सेंटीमेंट को मापने के लिए लेन-देन बेहतर संकेतक हैं। जबकि कोविड-19 झटके के दौरान आवास के लेन-देन में ज्यादातर गिरावट आई, अधिकांश चुनिंदा शहरों में उनकी कीमतों में गिरावट नहीं आई, बल्कि कुछ शहरों में तो आवासीय कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई ।

5.36 इसके अलावा, पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान गिरावट की तुलना में दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट भी बहुत कम रही है। चित्र 21क, पहले कोविड-19 लहर में और दूसरी- कोविड़ -19 लहर के दौरान पूर्व-महामारी स्तरों (अप्रैल-जून, 2019) से लेनदेन में परिवर्तन की तुलना करता है। लगभग सभी चयनित शहरों में पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट आई। हालाँकि, कोविड़ -19 की दूसरी लहर के दौरान, मुंबई, ठाणे, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में आवास लेनदेन पूर्व-महामारी के स्तर के सापेक्ष बढ़ गया। गांधीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, रांची, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी कोविड़ -19 लहर के दौरान आवास लेनदेन में गिरावट आई। हालांकि, यह गिरावट पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान हुई गिरावट से काफी कम रही है।

5.37 पहली और दूसरी कोविड़ -19 लहरों के दौरान तिमाही आवास लेनदेन में गिरावट के विपरीत, आवासीय संपत्तियों की कीमतों पर कोविड़ -19 के झटके का प्रभाव पूरे शहरों में एक समान नहीं था। चित्र 21ख पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान और पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी- कोविड़ -19 लहर के दौरान मूल्य सूचकांक में बदलाव की तुलना करता है। पहली कोविड़ -19 लहर के दौरान, गांधीनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, ठाणे,

मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में पूर्व-महामारी के स्तर पर आवास की कीमतों में वृद्धि हुई, और दिल्ली, नोएडा और रांची में आवास की कीमतों में कमी आई। पूर्व-महामारी के स्तर पर दूसरी कोविड् –19 लहर के दौरान भी इसी तरह के रुझान दिखाई दे रहे थे। अहमदाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर और रांची जैसे शहरों में आवास की कीमतें कोविड् –19 झटके के बावजूद बढ़ती रहीं।

चित्र 21(क): Q1 FY21 (पहली COVID-19 लहर) और Q1 FY22 (दूसरी COVID-19 लहर) में Q1 FY20 के पूर्व-महामारी स्तरों पर आवास लेनदेन में परिवर्तन

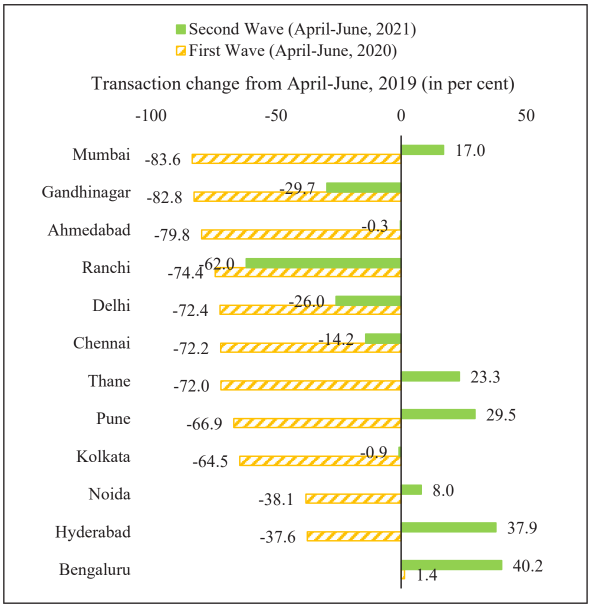

चित्र 21(ख): Q1 FY21 (पहली COVID.19 लहर) और Q1 FY22 (दूसरी COVID-19 लहर) में Q1 FY20 के पूर्व-महामारी स्तरों पर आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

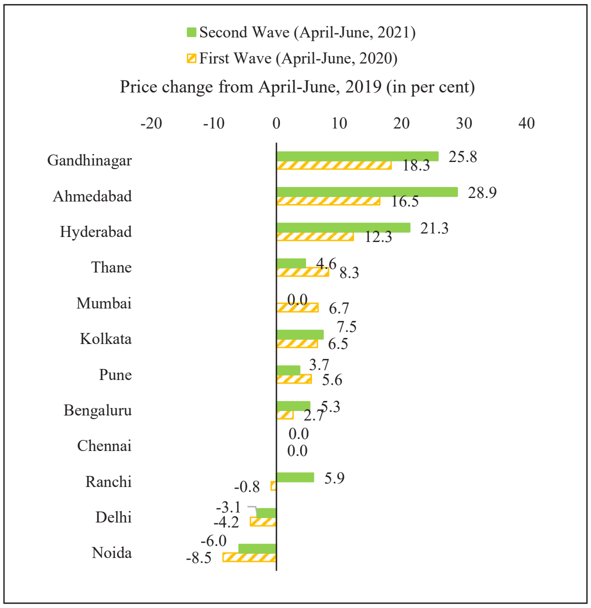

स्रोत: एनएचबी

5.38 दो कोविड् –19 तरंगों के बीच, जून 2020 से अप्रैल 2021 तक, आवास लेनदेन में तेजी से सुधार हुआ, क्योंकि त्रैमासिक खरीद सभी चयनित शहरों के लिए पूर्व-महामारी के स्तर को भी पार कर गई (चित्र 22)। आवास की मांग में यह वृद्धि संभवत: रुकी हुई मांग और सरकार द्वारा वहनीयता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के कारण है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिना बिकी आवासीय इकाइयों की संख्या में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। चित्र 23 चयनित शहरों में आवासीय संपत्तियों के आकार अर्थात कारपेट एरिया के आधार पर कीमतों को दर्शाता है।

चित्र 22: कोविड्-19 महामारी की दो लहरों के बीच 12 प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड संख्या में परिलक्षित रिकवरी

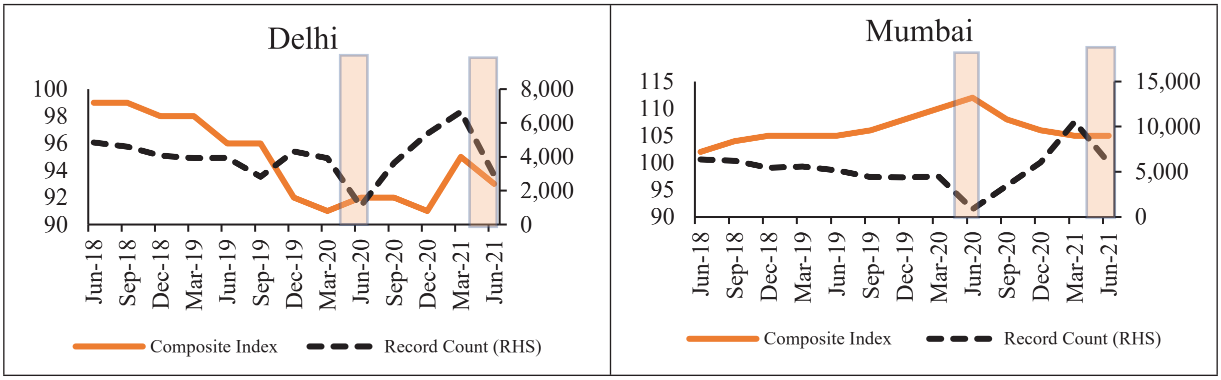

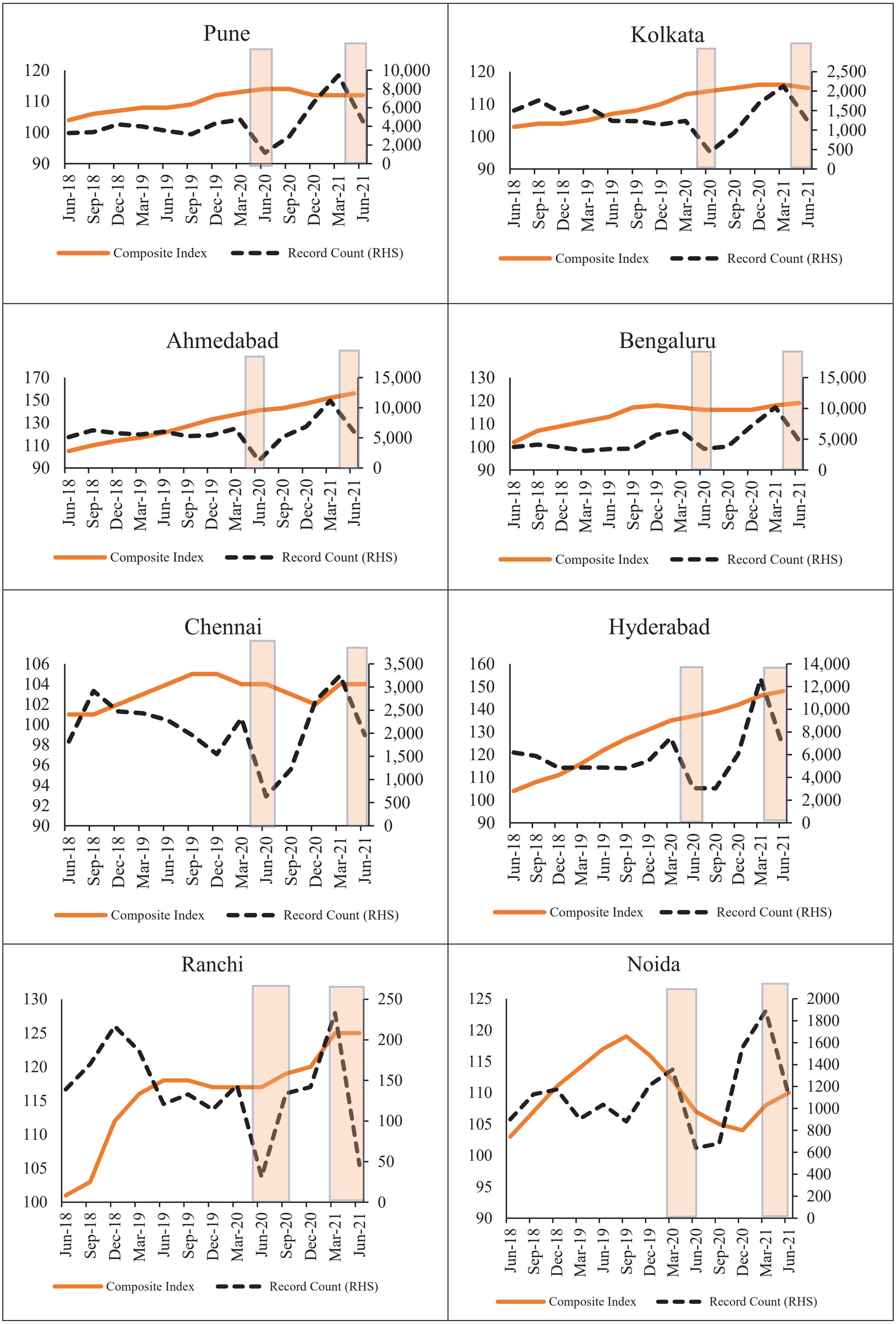
Pune
120
110
100
90
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Kolkata
120
110
100
90
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Ahmedabad
170
150
130
110
90
15,000
10,000
5,000
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Bengaluru
130
120
110
100
90
15,000
10,000
5,000
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Chennai
106
104
102
100
98
96
94
92
90
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Hyderabad
160
150
140
130
120
110
100
90
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Ranchi
130
125
120
115
110
105
100
250
200
150
100
50
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)
Noida
125
120
115
110
105
100
95
90
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
Composite Index
Record Count (RHS)

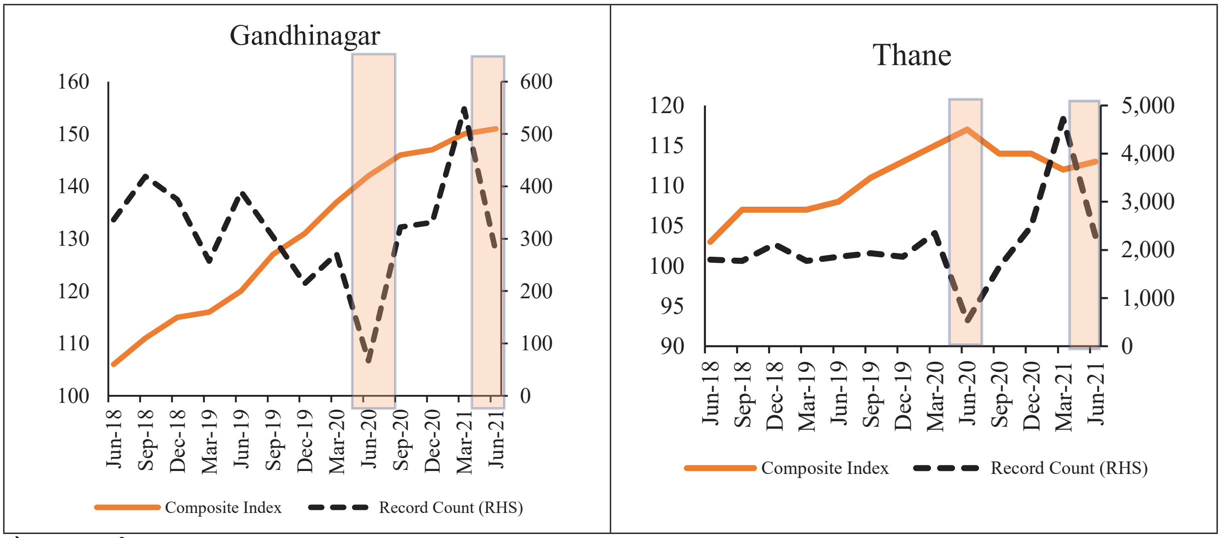

स्रोतः एनएचबी

चित्र 23: आवासीय संपत्तियों के आकार अर्थात कारपेट एरिया के आधार पर कीमतें

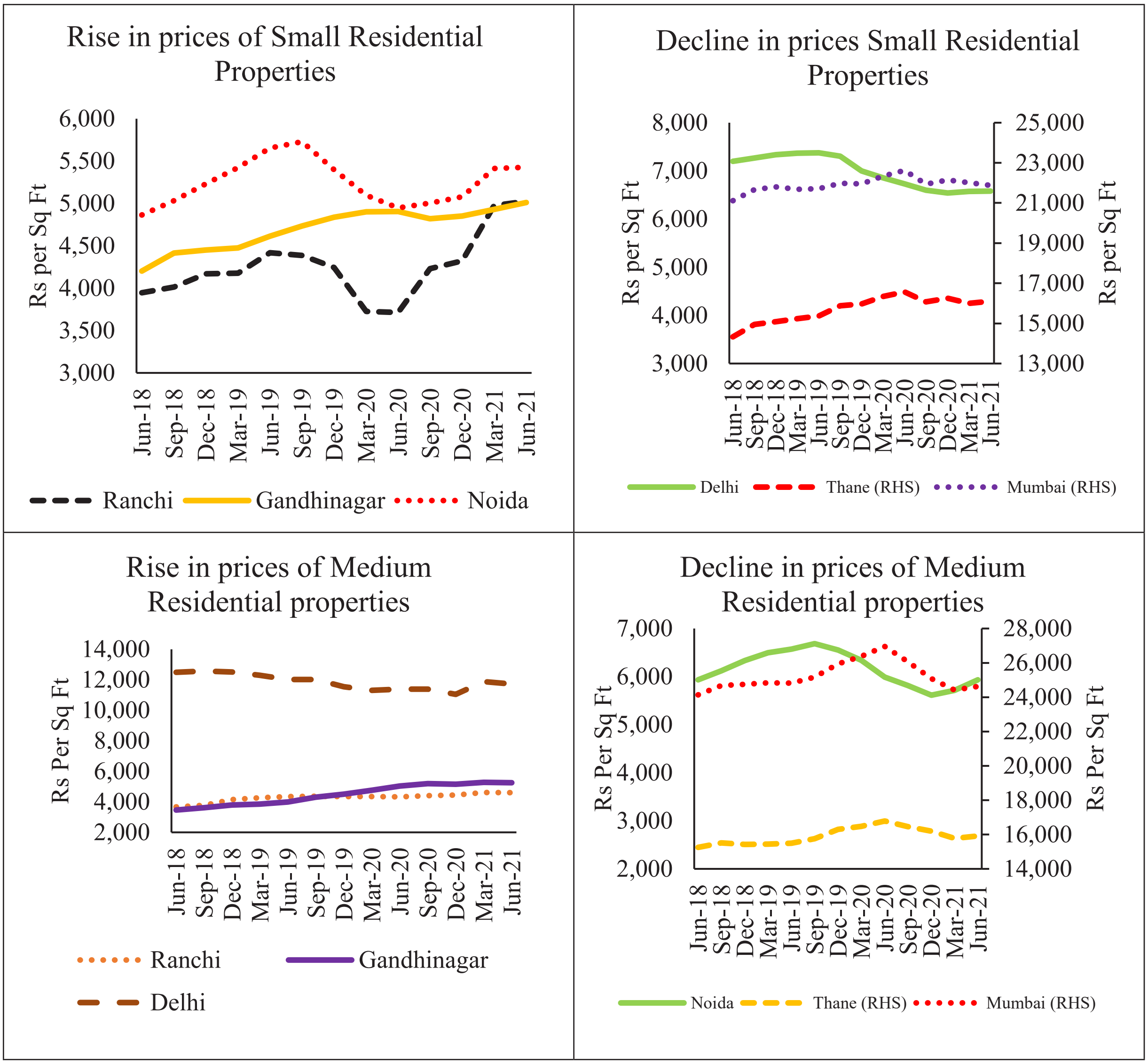

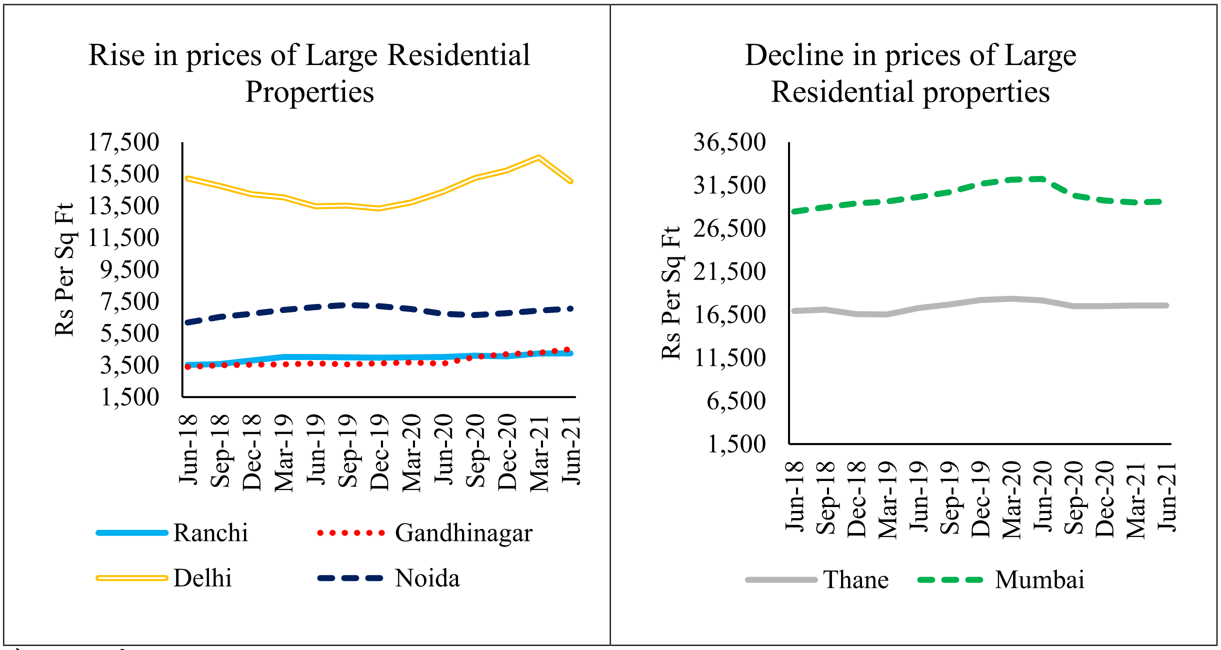

स्रोत: एनएचबी

नोट: छोटा आकार = [<=60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट)]; मध्यम= [>60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट) और <=110 वर्ग मीटर (1184 वर्ग फुट)]; बड़ी संपत्तियां (>110 वर्ग मीटर (1184 वर्ग फुट))।

दवा मूल्य निर्धारण

5.39 सरकार सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दवाओं के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करती है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए), फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) का एक संलग्न कार्यालय है जिसे दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए अधिदिष्ट किया गया है।

5.40 दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 355 दवाओं और 886 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2015 (औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अनुसूची-I) के तहत 31 दिसम्बर 2021 तक तय की गई थीं। इसके बाद, डीपीसीओ, 2013 के तहत 31 दिसम्बर 2021 को 1798 फॉर्मूलेशन/संविन्यासों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए थे। हाल ही के वर्षों के दौरान, जनहित में डीपीसीओ, 2013 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोरोनरी स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें भी तय की गई हैं। एनपीपीए ने फरवरी, 2019 में पायलट आधार पर चयनित 42 कैंसर रोधी गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।

कोविड़-19 प्रयास/पहल

- एनपीपीएने 3 जून 2021 को अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड हेल्थप्रोडक्ट्स (एससीएएमएचपी), पर नीति आयोग की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर (पीटीडीके स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स के लिए ट्रेडमार्जिन को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।
- 13 जुलाई, 2021 को पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन भी सीमित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन उपकरणों के अधिकांश ब्रांडों की कीमतों में 89 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

- कोविड़ प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश दवाएं अनुसूचित दवाएं हैं, जिनकी अधिकतम कीमत एनपीपीए द्वारा दी गई है। यहां तक कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं जैसे रेमेडिसविर के मामले में, जो कि कोविड़-19 प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, सरकारी हस्तक्षेप पर प्रमुख निर्माताओं/विपणकों द्वारा रेमडेसिविर के विभिन्न ब्रांडों के एमआरपी स्वेच्छा से कम कर दिए गए हैं।
- रेमेडिसविर, टोसीलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन के समान वितरण की निगरानी और समन्वय के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण का पालन किया जाता है।
- डीसीजी(आई) द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों पर किए जा रहे नियमित सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी भी की जा रही है। इसे मई 2021से मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा आयोजित कोविड-19 प्रबंधन दवाओं के साप्ताहिक उपलब्धता सर्वेक्षण के माध्यम से भी संपूरितकिया जा रहा है।

आपूर्ति संबंधी कारकों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य

भारत में मुद्रास्फीति के निर्धारण में आपूर्ति पक्ष के कारकों के महत्व को देखते हुए, लंबी अवधि की नीतियों से मदद मिलने की संभावना है।

1. **उत्पादन के पैटर्न में बदलाव:** किसानों को चावल और गेहूं की खेती से दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि देश दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर है और आयात निर्भरता को कम करने में भी मिलेगी। दलहन की ओर शिफ्ट होने से सरकार चावल और गेहूं के वास्तविक बफर स्टॉक को बनाए रखने में सक्षम होगी। हाल ही में, सरकार क्षेत्र विस्तार, एच वाई वी के माध्यम से उत्पादकता, एमएसपी (न्यूनतम मूल्य समर्थन) और खरीद के माध्यम से दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है।
2. **अंशांकित आयात नीति:** हालांकि बार-बार आयात शुल्क / टैरिफ संशोधन के माध्यम से दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए अनपेक्षित प्रतिक्रिया, उपभोक्ताओं को कम कीमतों के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करती है लेकिन इससे घरेलू उत्पादकों को गलत संकेत जाता है और एक अनिश्चितता का वातावरण तैयार होता है। अत: एक दीर्घकालिक सुसंगत दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा इस दिशा में एक कदम उठाया गया है, जहां म्यांमार के साथ 2.5 एलएमटी उड़द और 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए पांच साल के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मलावी के साथ 1 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए और मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एमओयू विदेशों में उत्पादित दालों और भारत को निर्यात की जाने वाली दालों की मात्रा में पूर्वानुमान सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार भारत को और दाल निर्यातक देश दोनों को लाभ होगा।
3. **जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन और भंडारण अवसंरचना पर ध्यान:** खराब मौसम में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि कृषि संबंधी उत्पादों और और अन्य खराब होने वाली आवश्यक वस्तुओं की बर्बादी को कम किया जा सके और खराब मौसम के चलते कीमतों में होने वाली उछाल से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके । इसके साथ ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विपणन संबंधी अवसंरचना की कमी को दूर करने की आवश्यकता है ताकि पैदावार ठीक होने पर या जरुरत से ज्यादा फसल तैयार होने पर किसानों मजबूरन/आपात बिक्री नहीं करना पड़े। खराब होने वाली वस्तुओं के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन संबंधी अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने और कृषि अवसंरचना कोष का प्रभावी उपयोग करने पर देश

में कृषि के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद मिल सकती है। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ग्रीन और किसान रेल जैसी योजनाओं का और अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. FAO. 2021. "FAO Food Price Index rises further in September". Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Accessed from:https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en
2. IMF. 2022. "World Economic Outlook, January, 2022". International Monetary Fund.
3. PIB. 2021. "In order to reduce the edible oil prices, Center reduces the duty on Crude Palm Oil (CPO) by 5%. Press Information Bureau, Government of India". Accessed from: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1731715
4. World Bank. 2021a. "Commodity Markets Outlook, April 2021"
5. World Bank. 2021b. "Commodity Markets Outlook, October 2021"
6. Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., &Terpenning, I. J. (1990). "STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess.", Journal of Official Statistics, 6(1), 3-33.
7. Reserve Bank of India. Monthly Bulletins